PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 259 ● भिलाई, शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

मालेगांव ब्लास्ट केस चार आरोपी हुए बरी

मुंबई। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द कर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। मालेगांव में इन धमाकों में 37 लोगों की जान चली गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की ओर से एक स्पेशल कोर्ट के सितंबर 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इस अपील में ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के तरीके और मामले में कई सह-आरोपियों को बरी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। फिलहाल, हाईकोर्ट ने जिन चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द किया है, उनमें राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा शामिल हैं। हाईकोर्ट के आज के फैसले से इन आरोपियों के खिलाफ मामला बंद हो गया और उनके खिलाफ चल रहा ट्रायल भी खत्म हो गया।

दादरी में पुलिस मुठभेड़ लूट-छिनैती का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाकिर पुत्र राजू के रूप में हुई है, जो दादरी कस्बे का ही निवासी है और लंबे समय से लूट व छिनैती के मामलों में वांछित चल रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना दादरी की पुलिस टीम बुधवार को क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक वांछित अपराधी नई बस्ती स्थित श्मशान घाट के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही भागने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त शाकिर घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

एनसीआर में गर्मी के साथ जहरीली हवा का डबल अटैक

नोएडा। एनसीआर के लोगों के लिए मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। जहां मार्च में फरवरी जैसी हल्की ठंडक का एहसास हुआ था, वहीं अब अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही मई-जून जैसी भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनने लगी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 22 और 23 अप्रैल को तापमान बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है।

चुनाव में टूटा रिकॉर्ड!

बंगाल में 89 तो तमिलनाडु में 82 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान....

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में मतदान थम गया है। पश्चिम बंगाल और पूरे तमिलनाडु में पहले चरण में हुई वोटिंग को लेकर वोटरों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग ने शाम 5:00 बजे तक दर्ज किए गए अनुमानित वोटिंग रुझान जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु में लगभग 82.24 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जबकि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में यह आंकड़ा लगभग 89.93 प्रतिशत रहा। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में शाम 5:00 बजे तक कुल वोटिंग लगभग 89.93 प्रतिशतदर्ज की गई। जिला-वार आंकड़ों के आधार पर, वोटिंग इस प्रकार दर्ज की गई: अलीपुरद्वार में लगभग 88.74 प्रतिशत, बांकुरा में 89.91 प्रतिशत, बीरभूम में 91.55 प्रतिशत, कूच बिहार में 92.07 प्रतिशत, दक्षिण दिनाजपुर में 93.12 प्रतिशत, दार्जिलिंग में 86.49 प्रतिशत, जलपाईगुड़ी में 91.20 प्रतिशत, झाड़ग्राम में 90.53 प्रतिशत, कलिम्पोंग में 81.98 प्रतिशत और मालदा में 89.56 प्रतिशत। इसके अलावा, मुर्शिदाबाद में 91.36 प्रतिशत, पश्चिम बर्धमान में 86.89 प्रतिशत, पश्चिम मेदिनीपुर में 90.70 प्रतिशत, पूर्वी मेदिनीपुर में 88.55 प्रतिशत, पुरुलिया में 87.35 प्रतिशत और उत्तर दिनाजपुर में 89.74 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। तमिलनाडु चुनाव की बात करें तो, चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में शाम 5:00 बजे तक कुल वोटिंग प्रतिशत लगभग 82.24 प्रतिशत दर्ज किया गया। जिला-वार आंकड़ों के आधार पर, मतदाताओं की भागीदारी इस प्रकार दर्ज की गई: अरियालुर में लगभग 83.09 प्रतिशत, चेंगलपट्टू में 82.41 प्रतिशत, चेन्नई में 81.34 प्रतिशत, कोयंबटूर में 82.33 प्रतिशत, कुड्डालोर में 81.91 प्रतिशत, धर्मपुरी में 87.28 प्रतिशत, डिंडीगुल में 86.35 प्रतिशत, इरोड में 87.59 प्रतिशत, कल्लाकुरिची में 84.22 प्रतिशत, और कांचीपुरम में 84.92 प्रतिशत। इनके अलावा, कन्याकुमारी में 73.44 प्रतिशत, करूर में 89.32 प्रतिशत, कृष्णागिरी में 82.40 प्रतिशत, मदुरै में 77.89 प्रतिशत, मयिलादुथुराई में 78.41 प्रतिशत, नागपट्टिनम में 83.15 प्रतिशत, नामक्कल में 87.63 प्रतिशत, पेरम्बलुर में 82.75 प्रतिशत, और पुदुकोट्टई में 81.55 प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी दर्ज की गई। वहीं, रामनाथपुरम में 74.41 प्रतिशत, रानीपेट में 86.28 प्रतिशत, सेलम में 88.02 प्रतिशत, शिवगंगा में 74.44 प्रतिशत, तेनकासी में 79.28 प्रतिशत, तंजावुर में 78.07 प्रतिशत, नीलगिरि में 75.90 प्रतिशत, थेनी में 78.73 प्रतिशत, तिरुवल्लुर में 80.70 प्रतिशत, और तिरुवरुर में 80.65 प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी दर्ज की गई। इसके अलावा, थूथुकुडी में 77.56 प्रतिशत, तिरुचिरापल्ली में 82.76 प्रतिशत, तिरुनेलवेली में 75.10 प्रतिशत, तिरुपत्तुर में 85.28 प्रतिशत, तिरुप्पुर में 86.33 प्रतिशत, तिरुवन्नामलाई में 85.59 प्रतिशत, वेल्लोर में 85.06 प्रतिशत, विलुप्पुरम में 85.45 प्रतिशत और विरुधुनगर में 82.16 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में चुनावों का दूसरा चरण 29 अप्रैल को निर्धारित है।

बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी पर हमला टीएमसी समर्थकों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के मतदान के दौरान व्यापक हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरों और लाठी-डंडे से हमला किया। वहीं मालदा में चुनाव अधिकारियों से हाथापाई और जामुड़िया में लावारिस गाड़ी में ईवीएम मिलने जैसे मामले सामने आए। अब दक्षिण मिदनापुर में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार पर हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेसके समर्थकों ने दौड़ा-दौड़ाकर सुवेंदु सरकार को पीटा। इस दौरान सुवेंदु जान बचाने के लिए भागते रहे। सुवेंदु सरकार पर हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ सुवेंदु को पीटती है। बताया जा रहा है कि सुवेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर 'बूथ जैमिंग' की जा रही है। जब वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, तो उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया गया। सुवेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा। वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने सभी लोगों की तुरंत गिरफ्तारी करने के आदेश दे दिए हैं। चुनाव आयोग ने पुलिस को वीडियो में मारपीट कर रहे सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इधर मुर्शिदाबाद के नाओदा में आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफहुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ है।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई ताकत

जर्मनी संग रक्षा सह-उत्पादन रोडमैप तैयार-राजनाथ सिंह..

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत और जर्मनी के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में महत्वपूर्ण बैठक की। तीन दिवसीय जर्मनी यात्रा पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय और जर्मन रक्षा उद्योग के दिग्गजों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस मुलाकात का मुख्य केंद्र बिंदु रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और सह-प्रौद्योगिकी उत्पादन रहा। यह बैठक रक्षा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब केवल हथियारों का खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह जर्मनी जैसी तकनीकी शक्तियों के साथ मिलकर उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहता है। राजनाथ सिंह ने जर्मन कंपनियों से आग्रह किया कि वे भारत की उदार निवेश नीतियों और रक्षा क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए माहौल अब पहले से कहीं अधिक अनुकूल है। जर्मन उद्योग जगत ने भी भारत के इन सुधारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से उन्नत और विशेष तकनीकों के क्षेत्र में साझा काम करने की बात कही। उनका मानना है कि इस प्रकार का सहयोग न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि इससे वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री की इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ हुई मुलाकात रही।

बॉयफ्रेंड के कपड़े उतारे, आंखों पर पट्टी बांधी और जिंदा जलाया

बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुलाया और वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल का बहाना बनाते हुए उसके कपड़े उतारे, आंखों पर पट्टी बांधी और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड को ज़िंदा जलाने के आरोप में 27 वर्षीय गर्लफ्रेंड को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक किरण और प्रेरणा पिछले लगभग 2 सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे किरण अपनी गर्लफ्रेंड प्रेरणा के घर पहुंचा था, क्योंकि प्रेरणा ने ही उसे अपने घर बुलाया था।

चुनावी माहौल के कारण कीमतें स्थिर

28 रुपये तक बढ़ने वाला है पेट्रोल-डीजल का रेट

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। क्रूड ऑयल पहले 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो युद्धविराम के बाद कुछ समय के लिए नीचे आया, लेकिन अब फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रिफाइनरियों को हर महीने लगभग 27,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चुनावी माहौल के कारण फिलहाल कीमतें स्थिर रखी गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।

झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी

पीएम मोदी ने कहा चार मई को बंगाल में बंटेगी मिठाई..

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की जमकर तारीफ की और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, 'मैं कह सकता हूं कि पिछले 50 वर्षों में यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है।' उन्होंने कहा कि पहले तो हर हफ्ते किसी को फांसी पर लटका देना और उसे आत्महत्या बता देना आम बात थी। यहां अराजकता और गुंडागर्दी का राज था। मैं चुनाव आयोग को हार्दिक बधाई देता हूं, उन्होंने एक बार फिर बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की गरिमा स्थापित की है। पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मुझे अब तक मिली जानकारी के आधार पर, मतदान पिछले सभी रिकार्ड तोड़ रहा है।' उन्होंने कहा कि कृष्णानगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। बरसों से जिनको आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा, 'झालमुड़ी मैंने खाई और मिर्ची टीएमसी को लग रही है।' उन्होंने कहा कि टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, स्थानीय नेताओं और उनके सिंडिकेट के खिलाफइतना गुस्सा है ।

हर-हर महादेव' के जयकारों के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट

रुद्रप्रयाग। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए गए। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड की दिव्य भूमि पर चारधाम यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।

जग्गी हत्याकांड केस में अमित जोगी को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे

रायपुर/ संवाददाता

अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर भी स्थगन आदेश जारी किया गया है। अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत दे दी है, जिससे उन्हें तुरंत जेल जाने से राहत मिल गई है। यह मामला वर्ष 2003 में रायपुर के मौदहापारा इलाके में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है। उस समय जग्गी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और विद्याचरण शुक्ला के करीबी माने जाते थे। साल 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपील पर लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील में हुई देरी को माफकरते हुए हाईकोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया था।

टिहरी में बड़ा हादसा

खाई में गिरी कार...आठ लोगों की दर्दनाक मौत

टिहरी/ एजेंसी

हरिद्वार अंत्येष्टि से घनसाली लौट रहा वाहन चंबा-कोटीकॉलोनी मोटर मार्ग पर नैल के पास अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया जिससे वाहन में सवार 10 में से आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भिलंगना ब्लॉक में नैलचामी क्षेत्र के चकरेड़ा गांव से 10 लोग हरिद्वार अंत्येष्टि में गए थे। लौटते समय दोपहर करीब 2.15 बजे वाहन चंबा-कोटीकॉलोनी मोटर मार्ग पर नैल गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। घटना का पता चलते ही चंबा थाना पुलिस और एसडीआरएफकी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने खाई में उतर कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दो घायलों को खाई से निकालकर जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचाया गया जबकि वाहन सवार आठ अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वाहन दुर्घटना की सूचना मिलने पर डीएम नितिका खंडेलवाल, विधायक किशोर उपाध्याय, एसएसपी श्वेता चौबे और सीएमओ डॉ. श्याम विजय ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचवाया। एसएसपी ने बताया कि दुर्घटना में घायल उत्तम कुमार (36) पुत्र पुस्सू मास्टर निवासी ग्राम लोस्तु बडियारगढ़ कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल और अंकित लाल (22) पुत्र आशा लाल निवासी ग्राम ठेला नैलचामी भिलंगना टिहरी को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया गया है। जबकि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। सीएमएस डॉ. अमित राय ने कहा कि प्राथमिक उपचार के बाद अंकित को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है जबकि उत्तम की स्थिति खतरे से बाहर है। दुर्घटना वाले स्थान पर काफी ढलान और तीखा मोड है लेकिन दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। इनकी गई जान 1- आशा लाल (40) पुत्र अषाडू निवासी ग्राम ठेला नैलचामी भिलंगना टिहरी। 2- विजय लाल (36) पुत्र भुरखिलया निवासी ग्राम ठेला नैलचामी भिलंगना। 3- प्रेमलाल (60) पुत्र संतूलाल निवासी ग्राम चकरेड़ा घटनसाली 4- महावीर (60) पुत्र विशु लाल निवासी चकरेड़ा घनसाली। 5- शिव सिंह (35) पुत्र पुष्कर सिंह वाहन चालक ग्राम होल्टा घनसाली। 6- सोहन लाल (65)गोपाल निवासी ग्राम चकरेड़ा घनसाली। 7- लक्ष्मण (65) पुत्र मुरखिलिया निवासी चांजी घनसाली। 8- शिनाख्त नहीं हो पाई।

सीएम धामी ने जताया शोक

इस हादसे की भयावहता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। उन्होंने घायलों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमें टिहरी गढ़वाल ज़िले के चंबा इलाके में नैल-कोटी कॉलोनी रास्ते पर एक गाड़ी के एक्सीडेंट की बहुत दुखद खबर मिली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों की आत्माओं को अपने श्रीचरणों में जगह मिले।

बेटी की डोली उठने से पहले उठी माता-पिता की अर्थी स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी की मौत

मुंगेली। मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बेटी के हाथ पीले करने का सपना संजोए एक दंपति की सड़क हादसे में मौत हो गई। घर में बेटी की शादी के लिए खरीदारी कर घर लौट रहे पति-पत्नी को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम लगरा के रहने वाले इंद्रेश्वर तिवारी (उम्र 56 वर्ष) और उनकी पत्नी देवेश्वरी तिवारी (उम्र 48 वर्ष) अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे। बीते शाम दोनों मुंगेली शहर से शादी के लिए जरूरी सामान और कपड़ों की खरीदारी कर अपनी बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। इस दौरान नवोदय विद्यालय ढाबे के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पति-पत्नी सड़क पर काफी दूर जा गिरे और गंभीर चोट आने की वजह से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही फास्टरपुर पुलिस मौके पर पहुंची।

दो माह पहले ही दूल्हा बना युवक, डौंडी ब्लॉक के युवक ने राजनांदगाँव में लिए फेरे, कलेक्टर के निर्देश पर ताबड़तोड़ कार्यवाही, शादी शून्य कराने की पहल

बालोद। जिले को भले ही कुछ माह पहले -बाल विवाह मुक्त जिला- घोषित किया गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत ने इस दावे की पोल खोल दी है। बुधवार को जिले से सामने आए एक मामले ने प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया, जब एक युवक ने 21 वर्ष की कानूनी उम्र पूरी होने से पहले ही विवाह कर लिया। मामला डौंडी ब्लॉक के ग्राम भरौंटोला-43 का है। यहां के निवासी योगेंद्र धनकर (उम्र 20 वर्ष 10 माह), पिता हेमलाल धनकर ने राजनांदगाँव जिले के ग्राम साल्हेटोला की युवती आशा धनकर, पिता भोजराम धनकर के साथ बुधवार तड़के करीब 4 बजे हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे ले लिए। विवाह राजनांदगाँव जिले में सम्पन्न हुआ, जिससे स्थानीय स्तर पर निगरानी तंत्र की सीमाएं भी उजागर हुईं। सुबह करीब 7 बजे जब बारात दूल्हे के गांव लौटी, तो खुशियों का माहौल ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। मामले की जानकारी मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग हरकत में आया और तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया।

कलेक्टर दिव्या मिश्रा के सख्त निर्देश पर प्रशासनिक टीम बिना देर किए गांव पहुंची। एसडीएम सुरेश साहू, तहसीलदार देवेंद्र नेताम, जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) समीर पांडे, बाल संरक्षण अधिकारी गजानंद साहू सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक के परिजनों को कड़ी समझाइश दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए युवक के पिता से लिखित सहमति पत्र लिया। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि युवक के 21 वर्ष पूर्ण होने तक युवती अपने मायके में ही रहेगी और वैधानिक आयु पूर्ण होने के बाद ही पुनः विधिवत विवाह सम्पन्न कराया जाएगा।

जागरूकता और निगरानी में अभी भी बड़ी खामिया

इधर, पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए बालोद कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने राजनांदगाँव कलेक्टर से संपर्क साधा और उक्त विवाह को शून्य घोषित कराने की मांग रखी है। सूत्रों के अनुसार, राजनांदगाँव प्रशासन भी इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। कार्रवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने गांव में जनजागरूकता अभियान भी चलाया। ग्राम पंचायत भवन की दीवार पर -बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है- का पोस्टर चस्पा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि बालोद जिले को लगभग 7 माह पूर्व बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद लगातार शपथ कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। बावजूद इसके, यह घटना दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता और निगरानी में अभी भी बड़ी खामियां मौजूद हैं।

मैदानी अमले की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े

विशेषज्ञों की मानें तो केवल घोषणाओं और औपचारिक अभियानों से सामाजिक कुरीतियों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए गांव-गांव तक सक्रिय निगरानी, सतत संवाद और प्रभावी जनजागरूकता बेहद जरूरी है। इस मामले ने महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक राहत की बात यह रही कि विवाह दूसरे जिले में सम्पन्न हुआ और युवती बालिग है, जिससे स्थिति को संभालने में प्रशासन को कुछ सहूलियत मिली। लेकिन यह घटना एक स्पष्ट संकेत है कि बाल विवाह जैसे मुद्दों पर अभी और अधिक गंभीरता और सतर्कता की आवश्यकता है।

राजनांदगांव प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे तीखे सवाल

संस्कारधानी जिले में पूरे हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुए बाल विवाह ने राजनांदगांव प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। तय उम्र से कम युवक की शादी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह दर्शाता है कि निगरानी व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ी है। चूंकि यह विवाह राजनांदगाँव जिले में हुआ, ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित जिला प्रशासन की भूमिका पर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर कैसे जिम्मेदारों की नजर से यह पूरा आयोजन बच गया..? क्या स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय था, या फिर लापरवाही इतनी गहरी है कि ऐसे मामलों की भनक तक नहीं लग पाती..? बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह एक गंभीर अपराध है, जिसमें आयोजकों, अभिभावकों और सहयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आना यह संकेत देता है कि जमीनी स्तर पर कानून का पालन सुनिश्चित कराने में बड़ी चूक हुई है।

खर्च कटौती की भेंट चढीं, कर्मचारी सुविधाएं : सीटू

दल्लीराजहरा। तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत तीसरे 17 अप्रैल को हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन (सीटू) के कार्यकर्ता, खदान के नियमित व ठेका श्रमिकों की समस्याओं व समग्र मांगों को लेकर माइंस ऑफिस के सामने दिन भर डटे रहे। खदान के अन्दर व बाहर व्याप्त समस्याओं व अव्यवस्था पर प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तेज गर्मी पर भी धरने मे डटे श्रमिकों ने कहा कि खदान प्रबंधन श्रमिकों के प्रति क्रूर व असंवेदनशील हो चुका है। इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए यूनियन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अपने अपने प्रभोशन को हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग के अधिकारियों के बीच खर्च कटौती की होड मची हुई है। और इसी होड़ में खदान के अन्दर व बाहर सभी जगह कर्मचारी सुविधाएं व लाभ अब तक के सबसे न्यूनतम व अमानवीय स्थिति तक पहुंच गये है।खदान के अन्दर केन्टीनों व कार्यस्थल में स्वच्छ पेयजल तक की सुविधा नहीं है।देश मे एलपीजी गैस की कमी को देखते हुए नाश्ते की वैरायटी को कम किया गया। लकडी से खाना नाश्ता बनाया ज रहा है।गैस आपूर्ति सुलभ होने पर भी अब तक पर्याप्त गैस उपलब्ध नहीं कराकर पैसे बचाये जा रहे हैं। भीषण गर्मी में कार्यरत श्रमिकों के लिए समुचित रेस्ट सेल्टर व पर्याप्त कूलर तक नहीं हैं। आवागमन के वाहनों में ए सी नहीं है।कई मशीनों के ए सी बंद पडे है। जबकि अधिकारियों के केबिन व वाहनों में एसी की कोई कमी नहीं है।पिछले तीन वर्षों से नान फाईनेंशियल रिवार्ड स्कीम केवल खदानों के लिए बंद है। सुरक्षा की स्थिति बेहद चिंता जनक है। दुर्घटनाओं पर कोई प्रभावी कार्य वाही नहीं हो रही है। अफसर ठेकेदारों के साथ मस्त है। अपनी योग्यता व निजी मेहनत से छत्तीसगढ़ स्तर के ट्रेड टेस्ट में स्थान बनाकर खदानों का नाम रोशन करनेवाले कर्मचारियों के लिये भी अब प्रबंधन द्वारा कोई सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया जाता है।वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी पदोन्नति की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर परीक्षा पास कर्मचारी को उचित प्रोत्साहन देकर उन्हें सही पदस्थापना नहीं दी जा रही। ठेका श्रमिकों को उचित श्रेणी का वेतन नहीं मिल रहा है। समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। आईपीडी मेडिकल सुविधा देने मे बार बार बहानेबाजी की जा रही । नाईट शिफ्ट , व माइंस एलाउंस बढाने की मां को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई ठेके बंद होने से ठेका मजदूर बेरोजगार हो गये हैं लेकिन प्रबंधन को कोई चिंता नहीं है। इसलिए प्रबंधन के इस नकारात्मक रवैया से आक्रोशित श्रमिकों ने अब आरपार के संघर्ष का मूड बना लिया है। हमारा यह तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन आन्दोलन का दूसरा चरण है।यदि प्रबंधन हमारी मांगो पर गंभीरता से सकारात्मक पहल नहीं करेगा तो अगले चरण का आन्दोलन और उग्र व विशाल होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। यूनियन के सचिव पुरषोत्तम सिमैया ने कहा कि बदतर होते टाउनशिप की स्थिति के लिए खदान प्रबंधन जिम्मेदार है। टाउनशिप के आवासों को अवैध कब्जे से मुक्त कर और खाली पड़े आवासों को सेवानिवृत कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों को आबंटित करने में कोई समस्या नहीं है, फिर भी प्रबंधन के अड़ियल रुख के कारण पूरा टाउनशिप अवैध कब्जे और अराजक तत्वों के आगोश में है। इसी तरह धीरे-धीरे माइंस हॉस्पिटल भी बदतर होते चला गया और आज यह हॉस्पिटल कहलाने के लायक भी नहीं बचा है। हमारी मांग है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमें चाहिए जिसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर पर्याप्त स्टाफ और सभी सुविधाएं होनी चाहिए इससे कम पर हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रबंधन को समझ लेना चाहिए कि यह संघर्ष थोड़ा कुछ हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि समग्र सुधार के लिए हम आगे बढ़े है और अंतिम दम तक संघर्ष जारी रहेगा। यूनियन के संगठन सचिव प्रकाश क्षत्रिय ने कहा कि जिन ठेका श्रमिकों के कंधे पर 70ब उत्पादन का बोझ है उन ठेका श्रमिकों को प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है। उनके लिए आईपीडी सुविधा की मांग, डीएवी स्कूल में एडमिशन एवं फीस में प्राथमिकता देने, तथा उचित श्रेणी का वेतन देने, नाइट अलाउंस 180 रुपए तथा माइंस भत्ता ?200 करने की मांग हम सालों से कर रहे हैं।

सीएमएचओ ने ली मितानिन कार्यक्रम के संबंध में जिला स्तरीय बैठक

मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी पर लाने दिया जोर

मुंगेली । सीएमएचओ डॉ. शीला साहा ने मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक समन्वयक एवं स्वस्थ पंचायत समन्वयकों की उपस्थिति में कार्यक्रम की प्रगति एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने कहा कि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मितानिनों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर नियमित घर-घर भ्रमण एवं एएनसी जांच सुनिश्चित करें, साथ ही जनजागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएमएचओ डॉ. साहा ने आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड एवं आभा आईडी निर्माण में मितानिनों से विशेष सहयोग करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला नोडल अधिकारी मितानिन कार्यक्रम डॉ. मनीष बंजारा ने मितानिनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे फील्ड स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अहम योगदान देती हैं और उनके प्रयासों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। बैठक में राज्य प्रोग्राम अधिकारी सत्यप्रकाश साहू, जिला मितानिन समन्वयक ललिता मरावी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार 2026: संतृप्तिकरण शिविर के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित

लंबित प्रकरणों को 30 अप्रैल तक निराकृत करने के निर्देश

मुंगेली । सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत संतृप्तिकरण शिविर के संबंध में जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों को शिविरों के सुचारू संचालन, आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी लंबित मामलों का समाधान 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध राहत मिल सके। बैठक में अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की हिदायत दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने में कोई कमी न रहे। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविरों को अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी एवं परिणाममूलक बनाना रहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिले में सुशासन को सशक्त बनाने और आमजनों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 01 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे।

इससे पहले सभी लंबित प्रकरणों का 30 अप्रैल 2026 तक निराकरण सुनिश्चित करने संतृप्तिकरण शिविर आयोजित करने के संबंध में इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन को मिला नया संरक्षक, इंद्रजीत सिंह छोटू की नियुक्ति

भिलाई। सेक्टर-6 में आयोजित 26वीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान समारोह में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह छोटू को छत्तीसगढ़ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन का संरक्षक नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इंद्रजीत सिंह छोटू ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में अपार संभावनाएं हैं और उचित मार्गदर्शन व संसाधन मिलने पर वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। इंद्रजीत सिंह छोटू ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि वे संरक्षक के रूप में खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने आयोजन समिति द्वारा सफल आयोजन के लिए सराहना करते हुए आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण साहू, कोषाध्यक्ष संतोष देवांगन सहित त्रिलोक सिंह, ए. नागभूषण, संतोषी माझी, पद्मिनी शर्मा, धारिणी जोशी, नामदेव साहू, महेश पटेल, आसिफ अली खान, अखिलेश पांडेय, लोमन सिंह, राजकुमार पांडेय, सुरेंद्र सूरी, अशोक पिल्लई, राज वासनिक, जयदीप साहू, अरुण गोयल, जे. भुनेश्वर राव, श्रीकांत, ममता रजक, प्रियांक मिश्रा, मुन्नू स्वामी, पीयूष टंडन, ब्लेसन बोस्को और पिंटू आर्या साहू सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। यह नियुक्ति न केवल एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलेगी।

ट्रैक्टर चलाकर कुलपति ने की बीज बोआई, अक्षय तृतीया पर मना 'अक्षित तिहार'

दुर्ग। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़) के उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, सांकरा-पाटन में अक्षित तिहार कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. रवि आर. सक्सेना रहे। विशिष्ट अतिथियों में कुलसचिव यशवंत केराम, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ. जितेंद्र सिंह एवं निदेशक शिक्षण एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. मंगल सिंह पैंकरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता डॉ. अमित दीक्षित ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति से खेत में बीज की बोआई की गई। इस दौरान कुलपति प्रो. रवि आर. सक्सेना ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर कृषि कार्य का शुभारंभ किया, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।इस अवसर पर कुलपति प्रो. सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि अक्षय तृतीया भारतीय संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो समृद्धि, शुभारंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को कृषि एवं परंपराओं से जुड़े रहने का संदेश दिया।

संबंधित विभागो को कलेक्टर ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश

सुशासन तिहार हेतु बैठक संपन्न

बलरामपुर । जिले में इस वर्ष भी आमजनों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'सुशासन तिहार 2026' का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन शिविरों का लक्ष्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित,पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है,ताकि उन्हें शासन-प्रशासन की सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिविरों के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से पुराने लंबित प्रकरणों और राजस्व से संबंधित लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर पेंशन,राशन,आय, जाति प्रमाण पत्र और सामाजिक सहायता पेंशन से संबंधित प्रकरणों को त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही,शिविरों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही जनकल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित न रह सके।

अनियमितता पर 05 कृषि केंद्रों में विक्रय पर लगा प्रतिबंध व 17 केंद्रों को नोटिस जारी

कृषि केन्द्रों का किया गया औचक निरीक्षण

मुंगेली ।कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला एवं विकासखंड स्तरीय टीमों ने जिले के विभिन्न कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अभियान के तहत कुल 43 कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर 05 कृषि केंद्रों में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया तथा 17 केंद्रों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही संबंधित संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि निर्धारित दर पर ही रासायनिक उर्वरकों का विक्रय करें तथा खाद के साथ अन्य सामग्री अनिवार्य रूप से न जोड़ें। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

25 अप्रैल को अतिक्रमण पर बुलडोजर, लेकिन 20 मीटर सड़क पर सिर्फ 3-3 मीटर कार्रवाई, रसूखदारों पर मेहरबानी

बालोद। शहर के बहुचर्चित अतिक्रमण हटाओ अभियान ने अब नया मोड़ ले लिया है। 25 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन पूरे दलबल के साथ सदर मार्ग सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण हटाने उतरेगा, लेकिन इस बार कार्रवाई से ज्यादा उसके बदले मापदंड चर्चा और सवालों के केंद्र में हैं। जहां पहले सख्ती के साथ पूरे दायरे में अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, वहीं अब सफेद पट्टी से दोनों ओर केवल 3-3 मीटर तक ही सीमित कार्रवाई का फैसला लिया गया है। यही बदलाव अब पूरे अभियान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जिस सदर मार्ग की चौड़ाई राजस्व रिकॉर्ड में 20 मीटर दर्ज है, वहां पूरी सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के बजाय केवल सीमित हिस्से में कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। शहर में चर्चा है कि क्या यह बदलाव महज तकनीकी है या फिर प्रभावशाली व्यापारियों और रसूखदारों के दबाव का नतीजा..? गौरतलब है कि इससे पहले झलमला से जिला अस्पताल तक एनएच-930, नए बस स्टैंड क्षेत्र और जय स्तंभ चौक से मधु चौक तक अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने कड़े मापदंड अपनाए थे। वहां किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई थी। लेकिन सदर मार्ग के मामले में अचानक नियमों का 'सॉफ्ट वर्जन' सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों की मानें तो शुरुआती स्तर पर सदर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी थी। नगर पालिका और राजस्व विभाग ने संकेत भी दिए थे कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा।

अतिक्रमणधारियों के अवैध कब्जों को नापकर चिन्हांकित किया गया। दुकान और घरों के अंदर तक अवैध कब्जे पाए गए। लेकिन जैसे-जैसे कार्रवाई की तारीख नजदीक आई, वैसे-वैसे मापदंडों में बदलाव होता गया और अब यह सीमित कार्रवाई के रूप में सामने आ रहा है।

तीन अलग अलग टीमों का गठन

इधर प्रशासन अपनी कार्रवाई को पूरी तरह जायज बता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में सुगम यातायात, आमजन की सुविधा और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है, जिसे खत्म करना जरूरी है। कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के विरोध या तनाव की स्थिति से निपटा जा सके। कार्रवाई 25 अप्रैल की सुबह 6 बजे से शुरू होकर पूरे दिन चलेगी।

क्या मापदंडों में यह बदलाव प्रशासन की मजबूरी..?

अपर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर पालिका, तहसील और अन्य विभागों को भी आपसी समन्वय के साथ अभियान को अंजाम देने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि निर्धारित सीमा के भीतर आने वाले ठेले, दुकानें, शेड या अन्य अवैध कब्जे यदि समय रहते नहीं हटाए गए, तो उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा और नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 25 अप्रैल का यह अभियान वास्तव में शहर को अतिक्रमण से राहत दिलाएगा या फिर '3 मीटर की कार्रवाई' के दायरे में ही सिमटकर रह जाएगा..? और क्या मापदंडों में यह बदलाव प्रशासन की मजबूरी है या फिर किसी दबाव की कहानी इस पर शहर की नजरें टिकी हुई हैं।

संक्षिप्त समाचार

महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का बीजेपी पर निशाना

रायपुर। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पास नहीं होने के बाद देशभर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस बीच रायपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला।रंजीत रंजन ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफनहीं है, बल्कि उसका विरोध परिसीमन बिल को लेकर है। उन्होंने कहा कि बिना जनगणना कराए परिसीमन करना सही नहीं होगा और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा किमहिला आरक्षण को 2023 में ही 543 सीटों पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे को टाल रही है।कांग्रेस सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है और वह इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही।वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए रायपुर में जनाक्रोश रैली निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए।इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रंजीत रंजन ने भाजपा की रैली को सिर्फ एक दिखावा करार दिया और कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे सियासी तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली समय सीमा की बैठक

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार 1 मई 2026 से सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाएंगे। सभी नगरीय निकाय और जनपद पंचायत के अधिकारी इस संबंध में सारी तैयारी निर्धारित अवधि में पूरी कर लें। कलेक्टर ने कहा कि 24 अप्रैल 2026 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर दीनदयाल सभागृह में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रमुख प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों को इस कार्यक्रम हेतु समुचित तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में हीट वेव चलने की संभावना है, इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाइयों का इंतजाम बनाए रखें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर एवं एडीएम श्री उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर में जल्द बिछेगी गैस पाइप लाइन, पीएनजी प्रोजेक्ट की तैयारी तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब रसोई गैस सिलेंडर के झंझट से जल्द राहत मिलने वाली है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना के तहत शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हरियाणा सिटी गैस कंपनी को सौंपी गई है। इसको लेकर नगर निगम मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना की तैयारियों और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने स्पष्ट निर्देश दिए कि काम शुरू करने से पहले एजेंसी को अनिवार्य रूप से निगम से एनओसी लेना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आयुक्त ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल पाइपलाइन को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां सड़क की खुदाई की जाए, वहां काम पूरा होते ही तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो। नगर निगम ने सभी जोन कमिश्नरों और नगर निवेश विभाग को एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं।

शादी के दौरान हादसा बिजली का खंभा गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत

रायपुर। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मंडप तैयार करने के दौरान बिजली का खंभा गिरने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, ग्राम खोखनिया निवासी मनोहर के घर विवाह कार्यक्रम आयोजित था। शादी की तैयारियों के तहत मंडप बनाया जा रहा था। इसी दौरान एक लकड़ी का खूंटा पास में लगे बिजली के खंभे के सहारे टिकाया गया था। बताया जा रहा है कि इसी कारण खंभा असंतुलित हो गया और अचानक गिर पड़ा। घटना के समय खंभे के पास ही खेल रहा तुषार, जो ग्राम चौरा निवासी मैनेजर का बेटा था, उसकी चपेट में आ गया। खंभा गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं।

पीएम जनमन एवं धरती आबा योजना की भी की गई समीक्षा

30 अप्रैल से पूर्व ऑनलाइन सीआर प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के दिए निर्देश-सचिव सोनमणि बोरा

- अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत स्वीकृत कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड अनुसार निर्धारित समयसीमा में करें पूर्ण : प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा

रायपुर/ संवाददाता

आदिम जाति, अनुसचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा है कि अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड अनुसार समयसीमा में पूर्ण किया जाए उन्होंने मई के प्रथम सप्ताह तक निर्माण कार्यों को अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। श्री बोरा आज मंत्रालय, महानदी भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं परियोजना प्रशासकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निर्माण कार्यों एवं अन्य विभागीय गतिविधियों का निरीक्षण करें। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कार्यों के सुचारू संचालन एवं आगामी लक्ष्यों हेतु दो सप्ताह के भीतर वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के PVTG बसाहटों वाले सभी 18 जिलों में निवासरत PVTG परिवारों का सर्वे कार्य कराया जा रहा है तथा प्राप्त जानकारी को मोबाइल ऐप सर्वे सेतु ऐप में अपलोड किया जा रहा है। आनॅलाइन पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वे कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में अग्रणी स्थान है। इसके लिए उन्होंने सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों को शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि यह पूरी प्रकिया विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में की जा रही है।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा स्वयं पूरी प्रकिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना है।

शासन की मंशा है कि PVTG समुदाय के प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के साथ पहुंचे तथा उनका शत प्रतिशत सैचुरेशन हो सके। उन्होंने कहा कि निश्चित ही भारत सरकार एवं राज्य शासन की यह पहल PVTG समुदाय के समग्र विकास और भविष्य की बेहतर नीतियों के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में संचालक, आदिम जाति अनुसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव श्री बी. के. राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, वित्तीय सलाहकार श्री नीरज मिश्रा, वित्त नियंत्रक श्री लाजरूस मिंज, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्री एल.आर. कुर्रे, श्री विश्वनाथ रेड्डी, श्रीमती मेनका चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चकवर्ती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा आधार बेस उपस्थिति प्रणाली एवं ई-ऑफिस व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन में कसावट एवं पारदर्शिता लाने तथा लालफीताशाही को दूर करने हेतु राज्य शासन द्वारा आधार बेस उपस्थिति प्रणाली एवं ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रदेश स्तर पर लागू किया गया है। अतः इसका सुचारू पालन मुख्यालय के साथ-साथ, टीआरआई, राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, विभाग अंतर्गत सभी आयोग एवं बोर्ड तथा जिलों में पदस्थ सहायक आयुक्त कायालयों में सुनिश्चित करवाया जाए। बैठक में ई-ऑफिस की भी समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता एवं कसावट के साथ-साथ लालफीताशाही को दूर करने में यह व्यवस्था बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। उन्होंने विभागीय योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभागीय अधिकारियों की प्रशंसा की एवं आगे भी इसी प्रकार समन्वय के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में सभी पूर्ण एमपीसी को 30 अप्रैल तक जिला कलेक्टर के अनुमोदन से विधिवत रूप से पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा द्वलहक्ष कर्मयोगी अभियान अंतर्गत 30 अप्रैल तक अनवार्य रूप से 03 पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए।

लू चलने के साथ आंधी तुफान और बिजली गिरने की चेतावनी

- छत्तीसगढ़ में एक साथ पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिकाएं सहित कई सिस्टम

रायपुर। संवाददाता

पूरे छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच अब मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिनमें पश्चिमी विक्षोभ, चक्रीय परिसंचरण और द्रोणिकाएं शामिल हैं। इनके प्रभाव से जहां एक ओर तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। रायपुर में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मध्य छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक ग्रीष्म लहर यानी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बस्तर और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। रायपुर में भी तापमान 42.8 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से चार से पांच डिग्री अधिक बना हुआ है, जिससे रात में भी राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने नारायणपुर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है।

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य युवक घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा। पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की ट्रक ने ही युवकों को रौंदा है। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार को अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी छेड़ीखेड़ी के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष पप्पू बंजारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में बैठकर उनका समर्थन किया।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची सरकार

वनाधिकार पट्टा और पीएम आवास से बदली मुरिया परिवार की जिंदगी

- नक्सल प्रभावित रहे बेदरे में खुशहाली की रोशनी, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुए बोगाम भीमा

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता और जनकल्याणकारी सोच का जीवंत उदाहरण सुकमा जिले के ग्राम पंचायत सिलगेर अंतर्गत आश्रित ग्राम बेदरे में देखने को मिला है। कभी घोर नक्सल प्रभावित रहे इस क्षेत्र में अब विकास और विश्वास की नई रोशनी फैल रही है। मुड़िया जनजाति के निवासी बोगाम भीमा पिता हिड़मा को शासन द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जो उनके जीवन में स्थायित्व और सम्मान की नई शुरुआत बन गया है।सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोगाम भीमा को 1.315 हेक्टेयर वनभूमि का वनाधिकार पट्टा मिला है। वर्षों से जिस जमीन पर वे खेती कर रहे थे, आज वह जमीन कानूनी रूप से उनकी हो गई है। अब वे निश्चिंत होकर धान की खेती कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवन बेहतर ढंग से चला पा रहे हैं। यह पट्टा उनके लिए केवल जमीन नहीं, बल्कि उनके अधिकार और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है।खुशियों की यह कहानी यहीं नहीं रुकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी पत्नी को पक्का मकान भी स्वीकृत हुआ है। कभी कच्ची मिट्टी के घर में बरसात और गर्मी झेलने वाला यह परिवार अब सुरक्षित और सम्मानजनक छत के नीचे जीवन जी रहा है। वर्षों पुराना सपना आज साकार हुआ है, जिससे उनके घर में खुशहाली और भरोसे का माहौल बना है।

रायपुर के 19 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

- ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति

रायपुर। संवाददाता

शहर में सुगम यातायात एवं आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर जिले में 19 प्रवेश मार्गों से शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड-01 एवं रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों से मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ हो गया है, जो 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कैनाल रोड प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, महावीर नगर चौक रिंग रोड 01, राजेंद्र नगर चौक रिंग रोड 01, पचपेड़ी नाका चौक रिंग रोड 01, संतोषीनगर चौक रिंग रोड 01, भाठागांव चौक रिंग रोड 01, कुशालपुर चौक रिंग रोड 01, रायपुरा चौक रिंग रोड 01, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग रिंग रोड 01, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग रिंग रोड, गोगांव तिराहा रिंग रोड नं. 02, गोंदवारा तिराहा रिंग रोड नं. 02, पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी, विधानसभा रोड स्थित व्हीआईपी तिराहा एवं एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं। शहर में पिछले कुछ समय से भारी वाहनों के कारण मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग रहा था। इससे स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

प्रेमी के घर में युवती ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार किए

रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 19 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान गुढ़ियारी निवासी 19 वर्षीय कविता दास के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना संतोषी नगर स्थित उसके प्रेमी महफूज़ खान के घर में हुई। पुलिस के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 को देर रात कविता और महफूज़ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद युवती ने कथित तौर पर फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महफूज़ खान कविता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और उसके साथ मारपीट भी करता था। इसी मानसिक प्रताड़ना के कारण युवती ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। टिकरापारा पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी महफूज़ खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 108 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारण और घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है।

गंगरेल बांध के उन्नयन को मिली नई रफ्तार...

- 65.5 करोड़ से बढ़ेगी बांध की उम्र
- डैम सेफ्टी पर फोकस, मरम्मत व संधारण कार्यो को हरी झंडी
- गंगरेल बांध के माध्यम से नहरों द्वारा धमतरी सहित कई जिलों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती

रायपुर/ संवाददाता

धमतरी जिले में स्थित रविशंकर सागर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, को अब उन्नयन और महत्वपूर्ण मरम्मत कार्यों के जरिए और अधिक सुदृढ़ व सुरक्षित बनाया जाएगा। राज्य शासन ने बांध की दीर्घकालिक सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती के लिए 65.5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल से न केवल बांध की आयु में वृद्धि होगी, बल्कि डैम सेफ्टी के मानकों को भी नई मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित कार्यों के अंतर्गत वर्टिकल प्रेशर ड्रेन की सफाई सहित अन्य आवश्यक संधारण कार्य किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बांध की आंतरिक संरचना सुदृढ़ होगी और जल रिसाव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। कलेक्टर ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने, गुणवत्ता मानकों के कड़ाई से पालन और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978 में निर्मित यह बहुउद्देशीय जलाशय पिछले लगभग चार दशकों से अधिक समय से क्षेत्र की जीवनरेखा बना हुआ है। गंगरेल बांध के माध्यम से नहरों द्वारा धमतरी सहित कई जिलों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इसके साथ ही यह जलाशय पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग और 11.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कलेक्टर ने कहा, रविशंकर सागर जलाशय केवल धमतरी ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवनरेखा है। इसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वीकृत कार्यों से बांध की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित होगी और सीपेज की समस्या का वैज्ञानिक समाधान किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनिटरिंग, गुणवत्ता परीक्षण और समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है।

पैंगोलिन बेचने 2 तस्कर पहुंचे रायपुर, वन विभाग की टीम ने पकड़ा

रायपुर। वन विभाग की टीम ने रायपुर में 50 करोड़ की पैंगोलिन के साथ दो तस्करों को पकड़ा है। दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के रहने वाले है। जब्त पैंगोलिन का कुल वजन 20 किलो बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम दोनों तस्करों के खिलाफ आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए आरोपियों का नाम प्यारेलाल गोपचे और गोखन हलदार है।

जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि भाठागांव के पास रावांभाठा, वालफेर्ट सिटी रायपुर के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी में दो आरोपीसंदिग्ध रूके हुए हैं। दोनों के पास जिंदा पैंगोलिन है। वन विभाग ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया।

ग्राहक बनकर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तस्करों को पैंगोलिन दिखाने को कहा। दोनों आरोपियों ने जिंदा पैंगोलिन दिखाई, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ बताई थी। सौदा होने के बाद कर्मचारी ने बाहर इंतजार कर रहे वन विभाग की टीम को इशारा कर झोपड़ी में आने को कहा।

टीम जैसे ही पहुंची तो आरोपी उन्हें देखकर घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें टीम ने दौड़ाकर पकड़ा। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 किलो वजनी पैंगोलिन जब्त की गई। वन विभाग की टीम ने बताया कि आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद से पिछले एक सप्ताह से उनकी तलाश कर रहे थे। कड़ी मेहनत के बाद दोनों आरोपियों को आज पकड़ा गया। दोनों आरोपी अलग-अलग जिले के रहने वाले है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

1-प्यारेलाल गोपचे, जिला बलाघाट (मध्यप्रदेश) में रहता है।

2- गोखन हलदार कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील का रहने वाला है।

संपादकीय

महंगाई -बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की जेब पर दोहरी मार

यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। यह विचित्र बात है कि एक ओर सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने का दावा करती है, तो दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी पर जरूरी खर्च में कटौती और आर्थिक परेशानियों के रूप में देखने को मिल रहा है। जब आय के साधन सीमित हों, तो आम आदमी की यही अपेक्षा होती है कि जरूरी वस्तुओं के दाम उसकी पहुंच में हों, ताकि परिवार के भरण-पोषण का संकट पैदा न हो।मगर हाल के वर्षों में आमदनी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, जितनी तेजी से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई मार्च में बढ़कर 3.4 फीसद हो गई, जबकि फरवरी में यह 3.2 फीसद के स्तर पर थी। खबरों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष से उत्पन्न संकट के कारण खुदरा महंगाई में वृद्धि हुई है। मगर सवाल है कि अगर सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित या स्थिर करने के लिए उचित कदम उठा रही है, तो फिर महंगाई में उछाल कैसे आ रहा है?यह बात छिपी नहीं है कि देश में सामाजिक स्तर पर आर्थिक असंतुलन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। रोजगार और आय के मामले में देश की बड़ी आबादी के लिए स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है। आमदनी में स्थिरता और घटती क्रयशक्ति की स्थिति में जब आवश्यक वस्तुओं पर आम लोगों का खर्च थोड़ा भी बढ़ता है, तो उनके लिए परेशानियां पैदा होना स्वाभाविक है। दरअसल, मार्च में महंगाई के आंकड़ों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा रहा।खुदरा महंगाई से इस बात का पता चलता है कि उपभोक्ताओं की खपत और खर्च की स्थिति क्या है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक अपनी नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई को ही आधार बनाता है। सरकार का दावा है कि खुदरा महंगाई अभी रिजर्व बैंक के चार फीसद के औसत अनुमान से नीचे बनी हुई है। मगर, यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर महंगाई दर चार फीसद के दायरे से ऊपर जाती है, तो फिर कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद भी कम हो जाती है।आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च में फरवरी की तुलना में महंगाई दर का बढ़ना पश्चिम एशियाई संकट के शुरुआती प्रभाव का संकेत है। यानी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का मोर्चा फिर से खुलता है और यह स्थिति लंबे समय तक रहती है, तो आवश्यक वस्तुओं के दाम किस तेजी से बढ़ेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में आलू-प्याज और कुछ दालों की कीमतों की महंगाई दर घटी है, लेकिन सोने-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई।बिजली, गैस और अन्य ईंधन श्रेणी में खुदरा महंगाई मार्च में 1.65 फीसद रही, जबकि फरवरी में यह 1.52 फीसद के स्तर पर थी। यानी आम लोगों के लिए राहत कम और मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। यही नहीं, शहरी इलाकों में 3.11 फीसद की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.63 फीसदी रही, जहां रोजगार और आय के साधन सीमित होते हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस उपाय नहीं किए, तो आने वाले दिनों में यह संकट और ज्यादा गहराएगा।

नारी शक्ति वंदन: विकसित भारत 2047 की आधारशिला

डॉ. पंकज शुक्ला
चेयरमैन ग्राम्या
प्रेसिडेंट- आर एस आर ई

भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ नारी की गरिमा और शक्ति उसके सांस्कृतिक एवं सामाजिक ताने-बाने की आधारशिला है। यह शाश्वत विचार– «यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता» अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ दिव्यता का वास होता है–आज भी भारत की विकास यात्रा का मार्गदर्शन कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, नारी सशक्तिकरण एक कल्याणकारी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राष्ट्र के विकास की केंद्रीय धुरी बन चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस परिवर्तन का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो भारत की समावेशी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और नारी-नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को दर्शाता है।

पिछले एक दशक में भारत ने शासन व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन देखा है, जहाँ महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नेता, उद्यमी और राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार बनकर उभरी हैं। यह परिवर्तन एक सशक्त और समन्वित नीतिगत ढांचे के माध्यम से संभव हुआ है, जिसमें जन-धन योजना के जरिए वित्तीय समावेशन, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरिमा और स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सुरक्षा और सम्मान, मुद्रा योजना के माध्यम से उद्यमिता, तथा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया गया है। ये सभी पहलें मिलकर नारी-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की मजबूत नींव तैयार करती हैं।

आज महिलाएं भारत की अर्थव्यवस्था में एक सशक्त योगदानकर्ता के रूप में उभर रही हैं। 8 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, लगभग 20 प्रतिशत स्वरूप्प उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित हैं, और कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान में महिलाओं का लुहुख में योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, जो उचित अवसर, संसाधन और बाजार उपलब्ध होने पर 30 प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि न केवल आर्थिक उन्नति को गति देगी, बल्कि भारत को वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी।

हालांकि, नीतिगत दृष्टि का वास्तविक प्रभाव तभी संभव है जब उसका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो। पिछले एक दशक में लहळ्ढ4ड्ढ के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्थानीय स्तर पर ठोस परिणामों में परिवर्तित किया जाए। 5 लाख से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए, स्वयं सहायता समूहों को उद्यमों में परिवर्तित किया गया, किसान उत्पादक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त किया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया।

हमारी पहलें–Mission Shakti, Mission Annapurna, Cooperative to Corporate, Village Development Committees (VDC), Poshan Abhiyan आधारित कार्यक्रम, «श्रृंगार बने हथियार» और «सोच से समृद्धि»–प्रधानमंत्री जी के «सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास» के सिद्धांत के अनुरूप समग्र परिवर्तन के मॉडल के रूप में कार्य करती हैं। ये पहलें महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं, जहाँ वे आर्थिक गतिविधियों की संचालक, स्थानीय संसाधनों को आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करने वाली उद्यमी, और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बनती हैं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने, बाजार तक सीधी पहुँच प्राप्त करने, डिजिटल और वित्तीय प्रणालियों से जुड़ने तथा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने में सक्षम बनाया गया है। इससे उनकी आजीविका न केवल स्थायी बनी है, बल्कि विस्तार योग्य भी हुई है। इसका प्रभाव बहुआयामी है–आर्थिक स्तर पर यह रोजगार सृजन, आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करता है, जबकि सामाजिक स्तर पर यह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। साथ ही, यह स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर समाज में समानता और सहभागिता की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस परिवर्तन को और अधिक सशक्त बनाता है, क्योंकि यह महिलाओं को शासन और नीति निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह केवल राजनीतिक भागीदारी का विस्तार नहीं, बल्कि महिलाओं को भारत के विकास की दिशा तय करने वाले नीति-निर्माता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज जब विश्व लैंगिक समानता की दिशा में प्रयासरत है, भारत एक ऐसा समग्र मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जो आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का संतुलित समन्वय करता है। यह मॉडल केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसर, क्षमता और नेतृत्व को केंद्र में रखता है।

जैसे-जैसे भारत विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती जाएगी। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण, समावेशी विकास सुनिश्चित करना और वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना–ये सभी लक्ष्य तभी संभव हैं जब महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास निरंतर और प्रभावी रूप से जारी रहें।

आगे की राह स्पष्ट है–शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और नेतृत्व विकास पर निरंतर निवेश करना होगा। जब महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त होती हैं, तो वे राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन जाती हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक सुधार नहीं, बल्कि भारत की सोच, शासन और विकास यात्रा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि महिलाएं केवल विकास की सहभागी नहीं, बल्कि उसकी सबसे सशक्त संचालक हैं।

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, उसकी गति और दिशा उसकी महिलाओं की शक्ति, संकल्प और नेतृत्व से निर्धारित होगी। और इसी शक्ति के माध्यम से भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि एक ऐसा वैश्विक नेतृत्व स्थापित करेगा जो समावेशी, संतुलित और मानवीय विकास की दिशा में मार्गदर्शन करेगा।

समाज और राष्ट्र में सत्यं शिवं सुंदरम् की स्थापना ही संघ का उद्देश्य

कृष्णमोहन झा/

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग स्थित श्री केशव स्मृति मंदिर में संघ के घोष पथक (बैंड मंडली) इतिहास पर आधारित हस्तलिखित ग्रंथ %राष्ट्र स्वराधना% के विमोचन समारोह के मंच से अपने उदबोधन में कहा कि संघ को अपने 100 साल के सफर में न तो किसी की कृपा की आकांक्षा रही न ही किसी की अव कृपा उसके सफर में कभी अवरोध पैदा कर सकी। स्वयंसेवकों के परिश्रम से संघ आज देश का दिशा दर्शन करने वाली ताकत बन चुका है। इसके बावजूद इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराने की संघ की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह अपने सभी कार्यों का श्रेय पूरे समाज को देना चाहता है। मोहन भागवत ने %राष्ट्र स्वराधना% ग्रंथ को संघ के स्वयंसेवकों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ कर वे यह जान सकेंगे कि संघ ने पिछले 100 सालों में क्या किया है और आगे क्या करना चाहिए। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों के परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संघ की विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रनिर्माण में समर्पित भाव से अपनी पूरी शक्ति लगाई है। इससे यह स्पष्ट है कि संघ केवल एक संगठन नहीं है बल्कि विचारधारा है जिसका मूल उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र की सेवा करना है।मोहन भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष को उत्सव के आयोजन नहीं बल्कि आत्मावलोकन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें पूर्वजों का स्मरण करते हुए और अधिक उन्नत स्थिति की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी है।संघ प्रमुख ने समाज को संगठित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और अधिक संगठित और व्यापक प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसमें समाज की भी सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया।

संघ प्रमुख ने घोष दल के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष दल में विभिन्न वाद्य यंत्र होते हैं जिनके स्वर एवं ध्वनि अलग अलग होते हुए भी स्वयं सेवक एक ही ताल पर चलते हैं। इससे समन्वय एवं एकता की भावना मजबूत होती है। जब कोई कार्य मन से एवं पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो उसका परिणाम भी उसी रूप में प्रकट होता है और सत्य शिवं सुंदरम् की अनुभूति होती है।मोहन भागवत ने अपनी इस बात को रेखांकित किया कि समाज और राष्ट्र में सत्यं शिवं सुंदरम् की स्थापना ही संघ का उद्देश्य है। सरसंघचालक ने कहा कि संघ के सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य संस्कारों का निर्माण करना है। सुदृढ़ शरीर और संस्कारित मन के समन्वय से गुणवत्ता पूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ना ही लक्ष्य है। इस दृष्टि से %राष्ट्र स्वराधना% का हस्तलिखित इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय बीत जाता है, कार्य खड़ा हो जाता है परन्तु मौलिक गुणवत्ता शुरुआत में थी उसे अंत तक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमने विकट परिस्थिति में कार्य कैसे खड़ा किया और किस उद्देश्य से किया उसका सदैव स्मरण कराने का कार्य यह ग्रंथ करेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवक पेशेवर गायक या वादक नहीं होते लेकिन अपने दैनिक कार्यों को संभालते हुए, बिना कागज सामने रखे इतनी सुंदर रचनाएं कैसे प्रस्तुत कर लेते हैं इस पर लोगों को आश्चर्य होता है परन्तु चमत्कार करना संघ का उद्देश्य नहीं होता ।वह तो अपने आप घटित हो जाता है। पूर्व स्वयं सेवकों के सद्गुण इन रचनाओं में मिलते हैं और दिखाई देते हैं। भाव तभी उत्पन्न होता है जब वादक पूरे मन से वादन करता है। इसे केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात समझ कर करना चाहिए।

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक है)

फांसी जैसी सजा से ही रुकेंगी पुलिस हिरासत में मौतें

(योगेंद्र योगी)

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं।

देश के न्यायालयों ने एक बार फिर पुलिस का वीभत्स चेहरा उजागर कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा के गठित किया गया पुलिस तंत्र किस कदर तानाशाह बन गया है, अदालतों के फैसलों ने इसे बेनकाब किया है। मदुरै की एक अदालत ने सातानुकुलम पुलिस स्टेशन में बाप-बेटे की मौत के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। तूतीकोरिन जिले के सातानुकुलम के व्यापारी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को 19 जून 2020 को कोरोना काल के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद 21 जून को दोनों को कोविलपट्टी जेल में रखा गया। 22 जून की रात करीब 9 बजे बेनिक्स की मौत हो गई, जबकि अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गई। इस मामले ने पूरे देश में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

इसी तरह लुधियाना जिले में करीब छह साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई थी। मौत के मामले में लुधियाना की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दीं। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी।

पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गईं। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया है। जुलाई 2024 को मध्यप्रदेश के बिलाखेड़ी निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने 8 लाख रुपये की कथित चोरी के आरोप में उसे हिरासत में लिया था। हिरासत में मौत के बाद उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके परिणामस्वरूप 15 मई को सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। इस जांच के सिलसिले में एजेंसी ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि हिरासत में हुई मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी फरार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी। 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है।कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की। जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा, केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं।

क्या नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक, प्रशासनिक व राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है?

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है। यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं।

(कमलेश पांडे)

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है।

हमारे देश के राजनेता भले ही चुनावों के दौरान दलित-महादलित-आदिवासी, ओबीसी-ईबीसी, अल्पसंख्यक-पसमांदा और गरीब सवर्ण आदि से जुड़े सामाजिक न्याय सम्बन्धी तरह-तरह की बातें करते हैं, मनगढ़ंत आंकड़े गिनाते/बताते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे श्रमजीवियों का अंतहीन शोषण होता रहता है, जिससे उनका मुंह फेरे रहना या फिर किसी बड़े आंदोलन के बाद सक्रिय होना उनके नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाता है।

आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मिलीभगत से किस कदर श्रमजीवी मजदूरों का शोषण अनवरत रूप से जारी रहता है और फिर एक दिन नोएडा मजदूर आंदोलन के शक्ल में फूट पड़ता है, इसका यह ताजा उदाहरण है। इसी प्रवृति से नई आर्थिक नीति विफलता के कगार पर खड़ी है। नीति निर्माण में नेताओं/नौकरशाहों ने जो पक्षपात दिखाया है, वह सभी समस्याओं की जड़ है।

यक्ष प्रश्न यह कि जिस देश में महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य और खर्चीला शहरी जीवन का बोलबाला हो, वहां पर निजी क्षेत्र के असमान वेतन स्तर के लिए हमारे नीति निर्माता जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन है, वही बताएं। विपक्ष का काम संसद में, विधान मंडल में इन्हीं पहलुओं पर तर्कसंगत बहस करना है, लेकिन वह भी नीतिगत नकारापन का शानदार नमूना बन चुका है। दिलचस्प तो यह कि पहले सत्ताधारी यूपीए के वक्त एनडीए विपक्ष में था और अब सत्ताधारी एनडीए के वक्त यूपीए/इंडिया गठबंधन विपक्ष में है।

चूंकि दोनों पूंजीवादी गठबंधन हैं और अपने आर्थिक मोहपाश में जनोन्मुखी समाजवादी व वामपंथी सियासत को बांध चुके हैं, जिससे सबकुछ गड्डमड्ड हो चुका है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद और कहीं सम्प्रदायवाद के नाम पर परस्पर बंटी हुई जनता को अपनी मौलिक जरूरतों का एहसास ही नहीं है।

काबिलेगौर है कि शहरों/महानगरों या गांवों में जो आमतौर पर वेतन स्ट्रक्चर होता है, उससे कोई युवा या वयस्क अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सकता है क्या? जवाब होगा- संभव नहीं! कोढ़ में खाज यह कि तरह तरह के मित्रों- शिक्षा मित्र, स्वास्थ्य मित्र आदि के मार्फत सरकारी क्षेत्र भी इन्हीं पूंजीवादी मानसिकता को तरजीह देता आया है, जिस पर उदार हृदय से बहस करने और भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने की जरूरत है।

सवाल है कि जिन शहरों में फ्लैट्स या जमीन की कृत्रिम कीमतें आसमान छूती हों, वहां के दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी, अंशकालिक/पूर्णकालिक श्रमिकों के वेतनमान, और भारतीय कानूनों से अधिकारियों/उद्योगपतियों के खिलवाड़ से पूरी श्रम व्यवस्था विस्फोटक कगार पर खड़ी है। शहरों में बढ़ता झुग्गी-झोपड़ी कल्चर किसी नैतिक महामारी जैसा प्रतीत होता है।

सुलगता सवाल है कि निजी क्षेत्र में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और पेंशन आदि की सुविधाएं निजी कम्पनियों में मिलती है। प्रोपर्टी इंडस्ट्री की तरह आधा ब्लैक सैलरी और आधा व्हाइट सैलरी वाली आंखों में धूल झोंकने वाली व्यवस्था से खुफिया तंत्र अनजान क्यों है? सरकारी क्षेत्रों की तरह आवासीय सुविधाओं से निजी क्षेत्र के श्रमिकों को वंचित क्यों रखा जाता है? नौकरी बाजार में श्रम ठेकेदार पैदा करने से किसके हित सधते हैं? सवाल अनेक हैं, लेकिन उत्तर एक- राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक सांठगांठ से जारी नीतिगत भ्रष्टाचार एक लाइलाज बीमारी है, जो किसी बड़ी जनक्रांति के बाद ही करवट लेगी।

जरा कल्पना कीजिए कि जब नरेंद्रमोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी मजदूर विरोधी परिस्थिति है तो पूर्व की सरकारों में कैसा जंगलराज रहा होगा, विचारणीय पहलू है। मजदूर शोषण कांड की एसआईटी और न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम भारतीयों के भविष्य के साथ एफडीआई आकर्षित करने के चक्कर में घोर अन्याय हो रहा है, जिससे बचे जाने की जरूरत है।

अब नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन के राजनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं। चूंकि नोएडा में मजदूरों का हिंसक आंदोलन वेतन वृद्धि की मांग पर केंद्रित है, जो हरियाणा की 35 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी से प्रेरित है। लिहाजा, योगी सरकार को तुरंत इसे लागू करना चाहिए। बताया गया कि यह प्रदर्शन फेज-2 होजरी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूरे नोएडा में फैल गया, जहां पेशेवर विपक्षी आंदोलनों के तर्ज और तोड़फोड़ और आगजनी हुई।

आंदोलन के पृष्ठभूमि की यदि बात की जाए तो मजदूर न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये तक बढ़ाने, बोनस और ओवरटाइम भत्ते की मांग कर रहे हैं। चूंकि हरियाणा से जुड़े एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों में असंतोष पैदा किया, क्योंकि यहां अनस्किल्ड वर्कर को 15,000 से कम वेतन मिलता है। यही वजह है कि योगी सरकार ने संवाद के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है और अविलंब इसके निर्णयों को लागू करने की जरूरत है।

जहां तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं की बात है तो योगी सरकार ने आंदोलन को साजिश, नक्सलवाद या राजनीतिक हाथ बताया, जिससे सहमत होना मुश्किल है, लेकिन आंदोलन के हिंसक होने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलत भी नहीं हैं। वहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की पूंजीपति पक्षधर नीति को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर शोषण का आरोप लगाया, जो अतिरेक है। चूंकि कांग्रेस और सपा ने सरकार की आलोचना की, इसलिए केंद्र भी सतर्क है।

इस अप्रत्याशित आंदोलन का प्रमुख निहितार्थ यह है कि यह आंदोलन श्रम नीतियों पर बहस तेज कर सकता है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के फैसलों से अंतरराज्यीय दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष को मजदूर वोट बैंक मजबूत करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को कानून-व्यवस्था पर खुद को साबित करने की चुनौती बढ़ी।दिल्ली-एनसीआर में इसके फैलाव का खतरा है, जो आगामी चुनावों में यदि बड़ा मुद्दा बना तो सत्ताधारी भाजपा के लिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव में राजनीतिक मुश्किलों का कारण बन सकता है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार समय रहते ही सचेत हो जाएं। इसी में राजनीतिक बुद्धिमानी होगी। यह कोरा सच है कि नोएडा मजदूर हिंसक आंदोलन के लिए औद्योगिक-प्रशासनिक-राजनीतिक सांठगांठ जिम्मेदार है। नोएडा मजदूर आंदोलन 2027 यूपी विधानसभा चुनावों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह श्रमिक असंतोष को विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना रहा है। हालांकि अभी ताजा घटना होने से विश्लेषण अनुमानित है, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा है। इससे विपक्ष को लाभ मिलता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की पूंजीपति नीति बताकर मजदूरों का समर्थन किया, जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, और विपक्षी एकता का संकेत दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक वोट (गौतमबुद्धनगर सीटें) प्रभावित हो सकते हैं। इससे भाजपा की जमीनी चुनौती बढ़ेगी और हिंदुत्व दम तोड़ देगा, इसलिए योगी सरकार ने वेतन, ओवरटाइम सम्बन्धी निर्देश देकर क्षतिपूर्ति की कोशिश की, लेकिन इसे साजिश बताकर विपक्ष को और हवा मिली। कानून-व्यवस्था का सवाल उठा, जो भाजपा के मजबूत सरकार वाले नैरेटिव को कमजोर करता है। इससे दिल्ली-एनसीआर में आंदोलन के फैलाव से पश्चिम यूपी की सीटें जोखिम में पड़ सकती हैं। वहीं, श्रम मुद्दा, बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी से जुड़कर 2027 में प्रमुख हो सकता है, खासकर ग्रेटर नोएडा-जेवर जैसे क्षेत्रों में। इसलिए यदि समाधान न हुआ तो विपक्ष मजबूत, वरना भाजपा इसे विकास के पक्ष में पलट सकती है। कुल मिलाकर, नोएडा रणभूमि बन चुका है।वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के समर्थन में उतरा सर्व समाज, रैली निकाल कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तावित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को लेकर प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के सर्व समाज ने एकजुट होकर इस विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है। इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और पूर्वजों की धरोहर की रक्षा के लिए इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं। नारायणपुर का सर्व समाज चाहता है कि प्रलोभन और दबाव के खेल को समाप्त किया जाए। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर इस कदम को ऐतिहासिक बताया। ज्ञापन में सर्व समाज ने उल्लेख किया है कि यह विधेयक विशेष रूप से जनजाति समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि नारायणपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अपनी परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए इस कानून की अत्यंत आवश्यकता है। सर्व समाज ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन की कार्यप्रणाली और जिले में हो रही गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की है। प्रशासन द्वारा मतांतरित लोगों की संख्या शून्य दिखाए जाने पर समाज ने असंतोष जताया है।जिले के अनेक गांवों में तेजी से हो रहे प्रार्थना गृहों के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। सर्व समाज ने दावा किया है कि वे प्रशासन को उन प्रचारकों (पास्टरों) की सूची भी उपलब्ध कराएंगे जो प्रलोभन के माध्यम से मतांतरण की गतिविधियों में संलिप्त हैं।रविवार और अन्य त्योहारों के अवसर पर होने वाली विशेष प्रार्थना सभाओं में बढ़ती भीड़ को लेकर भी संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। नारायणपुर वासियों ने स्पष्ट किया कि प्रलोभन के माध्यम से हो रहे मतांतरण को रोकना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अस्तित्व का विषय है। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी सूचनार्थ सौंपी गई है, जिसमें प्रार्थना गृहों और संबंधित प्रचारकों की विस्तृत सूची संलग्न की गई है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रुपसाय सलाम ,नारायण मरकाम, इंद्र प्रसाद बघेल, बृजमोहन देवांगन , नारायण प्रसाद साहू ,गुलाब बघेल,संध्या पवार, रामशीला नाग, मंगाऊ कावड़े, प्रेमनाथ उसेंडी, आलोक झा, लच्छन कगि, सनवारिन पोटाई, सुखराम करंगा,अनिल साहू, संतनाथ उसेंडी, चैतराम कुमेटी, बुधराम कोर्राम, सूर्यपाल दुबे, सुखयारी सलाम, सुकमन कोर्राम, सोनसिंग कोर्राम, राजू दुग्गा, परमानंद नाग नानू ,सुकमन कचलाम, मनीराम सलाम, गोपाल दुग्गा, अमलू नाग, दिपेन्द्र भोयर, रामसाय दुग्गा, बिंदेश्वर महावीर,अंकालू दुग्गा,लछराम साहू, टेटकू राम साहू, सहित विभिन्न ग्रामों से ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में जुड़े 13 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार

कोण्डागांव। हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल के नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है।

हरा सोना संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम- वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। वर्ष 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं।

लगभग 11 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण होने की संभावना- बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। बस्तर संभाग में वर्ष 2025 के 3.90 लाख परिवारों की तुलना में इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4.04 लाख हो गई है। इस साल अब तक 14 हजार 57 नए परिवार इस कार्य से जुड़े हैं।

10 नए फड़ और बेहतर तैयारी- नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है, जहां 2100 से अधिक मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है। इसके अलावा सुकमा और केशकाल क्षेत्रों मंक भी नए फड़ जोड़े गए हैं। पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधाओं के कारण 351 फड़ों में संग्रहण नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष सभी फड़ों में कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

सुगम संचालन और पारदर्शी भुगतान- संग्रहण कार्य को सुचारू बनाने के लिए संग्राहक कार्ड, बोरा, सुतली, गोदाम और परिवहन जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही तेन्दूपत्ता के भंडारण का बीमा भी कराया जा रहा है।

बस्तर मुन्ने 'अग्रणी बस्तर' और नियद-नेल्लानार 2.0 से बीजापुर में विकास को मिलेगी गति : कलेक्टर संबित मिश्रा

बीजापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त होने के बाद विकास कार्यों में तेजी लाने दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन होने जा रहा है जिसमें बस्तर मुन्ने जिसका गोंडी में शाब्दिक अर्थ है अग्रणी बस्तर और दूसरा योजना नियद नेल्लनार 2.0 इस अभियान का मूल उद्देश्य एनसीएईआर सर्वे में नियद नेल्लनार अंतर्गत 31 जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पाए गए परिवारों को शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। बस्तर मुन्ने अभियान के तहत सभी गांवों में मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीणों के मांग पर प्राथमिकता के साथ मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली पानी सड़क अस्पताल मोबाइल टावर जैसे प्रमुख 8-10 अधोसंरचना को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिसको ग्राम सभा के माध्यम से यह तय किया जाएगा कि गांव के विकास के लिए पहले तीन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रस्ताव पारित होगा जिसे निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण भी किया जाएगा। वहीं पूर्व में नियद नेल्लनार अभियान के तहत पुलिस सुरक्षा कैंप 10 किलोमीटर की परिधि वाले गांव को शामिल किया गया था। किंतु अब बीजापुर नक्सल मुक्त होने से नियद नेल्लनार 2.0 के तहत जिले के सभी गांव और ग्राम पंचायत दायरे में आ गया है। जिसमें 31 व्यक्ति मूलक योजनाओं, 14 सामुदायिक सुविधाएं और 10 वांछित योजनाओं के कार्य शत-प्रतिशत सैचुरेशन किए जाएंगे। कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि उक्त योजनाओं को जमीनी स्तर शत-प्रतिशत सैचुरेशन करने मैदानी अमला एक सप्ताह तक गांव में रहकर सभी हितग्राहियों से डोर-टू-डोर मिलेंगे और सर्वे करेंगे तत्पश्चात शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करेंगे। यह सर्वे 27 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें पहले चरण में 80 गांव शामिल होगा और सभी गांवों में क्रमशः होगा। कलेक्टर मिश्रा ने उक्त अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं जिला जनपद एवं पंचायत स्तर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यों तथा जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने को कहा है।

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली को समर्पित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया

नारायणपुर। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 के अवसर पर छेटेडोंगर लौह अयस्क खदान मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जे.एन.आई.एल.) में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली को समर्पित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष पृथ्वी दिवस 2026 की थीम 'हमारी शक्ति, हमारा ग्रह' के अनुरूप, खदान परिसर में सतत भूमि संरक्षण एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करने, स्वच्छता और पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छेटेडोंगर खदान और निको माइनिंग कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों ने सतत भूमि संरक्षण की शपथ ली तथा छेटेडोंगर खदान परिसर और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। इस अवसर पर जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, निरंतर स्वच्छता अपनाने और धरती को प्रदूषण-मुक्त रखने का संदेश दिया गया। पृथ्वी एवं प्रकृति के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु पृथ्वी दिवस 2026 की थीम पर आधारित चित्रकला, स्लोगन और कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह आयोजन आशीष मिश्रा, उपाध्यक्ष (खान) के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छेटेडोंगर खदान एवं निको माइनिंग के सभी विभाग प्रमुखों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और पृथ्वी के संरक्षण हेतु अपने संकल्प को दोहराया। छेटेडोंगर लौह अयस्क खदान मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जे.एन.आई.एल.) की यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि सामूहिक प्रयासों से ही हम अपने पृथ्वी एवं पर्यावरण को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बना सकते हैं।

किरंदुल के विकास को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने एनएमडीसी सीएमडी अमिताव मुखर्जी से की चर्चा

किरंदुल । किरंदुल नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष बबलू सिद्दकी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह ने नगर की बढ़ती समस्याओं और जनसुविधाओं को लेकर एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी से विस्तृत चर्चा की एवं नगर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।चर्चा में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि किरंदुल नगर में भारी वाहनों (ट्रकों) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बस स्टैंड से 04 नम्बर पेट्रोल पंप तक की सड़क पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।भारी ट्रकों के लगातार आवागमन से सड़क धीरे-धीरे धंस रही है, जगह-जगह गड्ढे बन रहे है, जिससे आम नागरिकों, दोपहिया चालकों एवं राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इस स्थिति को देखते हुए उक्त मार्ग पर मजबूत एवं टिकाऊ आरसीसी सड़क (कंक्रीट रोड) का निर्माण अत्यंत आवश्यक बताया गया, ताकि लंबे समय तक सड़क सुरक्षित और सुचारू बनी रहें।इसके साथ ही चर्चा में एक और अहम मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि नगर के भीतर से होकर गुजरने वाले ट्रकों की बढ़ती आवाजाही न केवल यातायात व्यवस्था को बाधित कर रही है, बल्कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है।ऐसे में किरंदुल नगर के बाहर से होकर गुजरने वाली एक बाईपास सड़क का निर्माण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। बाईपास सड़क बनने से भारी वाहनों का दबाव शहर के अंदर कम होगा, जिससे सड़कें सुरक्षित रहेंगी,जाम की समस्या घटेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।साथ ही यह कदम नगर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।इसके अलावा, बस स्टैंड से पेट्रोल पंप तक सुव्यवस्थित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था स्थापित करने एवं नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई, ताकि क्षेत्र स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बन सके। चर्चा में यह भी बताया गया कि सीएसईबी रेल्वे कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 18 में पहले संचालित हो रही स्कूल बस सेवा को बंद कर दिया गया है,जिससे छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।इस सेवा को पुनः प्रारंभ करने की मांग करते हुए बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। अंत में एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जनहित के इन महत्वपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

बीएसपी प्रबंधन एवं रावघाट माइंस की वादाखिलाफी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित

नारायणपुर। नारायणपुर जिला में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन एवं रावघाट माइंस द्वारा लगातार की जा रही वादाखिलाफी को लेकर प्रभावित गांवों के ग्रामीणों में बढ़ता असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। तेलसी मोड़ क्षेत्र में राजाराव बूढ़ादेव गोंद ग्राम विकास समिति रावघाट के बैनर तले ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। आंदोलन को परिवहन संघ और विभिन्न श्रमिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। राजाराव बूढ़ादेव गोंद ग्राम विकास समिति रावघाट के पदाधिकारियों एवं प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि रावघाट क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने से पहले भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा खदान शुरू होने के समय करीब 900 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, जबकि अब तक लगभग 180 लोगों को ही काम मिल पाया है। उन्होंने मांग की है कि रावघाट प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को बीएसपी, माइनिंग कंपनियों और परिवहन कंपनियों में 100 प्रतिशत रोजगार कोटा दिया जाए। साथ ही बीएसपी और सेल की स्थायी भर्तियों में 10 प्रतिशत पद आरक्षित कर पहले प्रभावित गांवों, उसके बाद आसपास के गांवों और फिर जिले के अन्य युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा सीएसआर और डीएमएफ फंड के माध्यम से स्थानीय युवक-युवतियों को नर्सिंग, आईटीआई, ड्राइविंग और माइनिंग से जुड़े प्रशिक्षण देकर हर वर्ष 100 से 200 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई है। ग्रामीणों ने पर्यावरणीय नुकसान को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि माइंस से निकलने वाला 'लाल पानी' खेतों और जल स्रोतों में मिल रहा है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं की अनुमति और वन अधिकार कानून के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि डीएमएफ की 70 प्रतिशत राशि सीधे प्रभावित ग्राम पंचायतों के विकास में खर्च की जाए और इसकी मासिक आय-व्यय रिपोर्ट समिति को लिखित रूप में दी जाए। साथ ही आगामी एक वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए तथा क्षेत्र में डीएवी स्कूल और अस्पताल के निर्माण के लिए निगरानी समिति गठित कर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। परिवहन व्यवस्था को लेकर भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने कई मांगें रखी हैं। इनमें रावघाट से अंतागढ़ तक सड़क परिवहन दर प्रति टन 910 रुपये निर्धारित करने, परिवहन का भुगतान हर माह की 5 तारीख तक सुनिश्चित करने तथा देरी होने पर 18 प्रतिशत ब्याज देने की मांग शामिल है। इसके अलावा रेल परिवहन शुरू होने के बाद भी सड़क मार्ग से कम से कम 40 प्रतिशत खनिज परिवहन जारी रखने और डीजल दरों के अनुसार परिवहन भाड़े में वार्षिक वृद्धि की मांग भी की गई है।श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को भी आंदोलन में प्रमुखता दी गई है। ग्रामीणों ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ VDA, PF, ESIC, ओवरटाइम, मेडिकल अलाउंस, बीमा, यात्रा भत्ता, हाउसिंग भत्ता और बोनस जैसे सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित करने तथा हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करने की मांग की है। साथ ही मृतक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने और स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन का भुगतान बीएसपी द्वारा किए जाने की मांग भी उठाई गई है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और स्पष्ट कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय राज्य मंत्री साहू 26 को करेंगे सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण

बिलासपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जूदेव जी शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में अत्याधुनिक रक्त केंद्र, माइक्रोबायोलॉजी, हार्मोन लैब तथा एआई पावर्ड माइक्रोस्कोपी यूनिट का लोकार्पण करेंगे। एनटीपीसी सीपत द्वारा सीएसआर मद के अंतर्गत लगभग 4.27 करोड़ रुपये के उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस आशय की जानकारी अस्पताल के संयुक्त संचालक सह चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा दी गई। इस अवसर पर विशिष्ट उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल होंगे। साथ ही विधायक सर्वश्री धरम लाल कौशिक, अमर अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एनटीपीसी सीपत के परियोजना प्रमुख श्री स्वपन कुमार मंडल शामिल होंगे।

खूंटाघाट से 25 अप्रैल को छोड़ा जाएगा पानी, निस्तारी के लिए 107 गांवों के 211 तालाब भरे जाएंगे

बिलासपुर। जिले में बढ़ती जल आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन ने खूंटाघाट जलाशय से नहरों के माध्यम से गांवों के निस्तारी तालाब भरने का निर्णय लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा 25 अप्रैल को सवेरे 11 बजे से खारंग जलाशय के बाएं और दाएं तट की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। नहर किनारे बसे 107 गांवों के 211 तालाबों को भरने की योजना बनाई गई है। यह निर्णय जनप्रतिनिधियों की मांग और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि नहर के पानी का उपयोग केवल निस्तारी तालाब भरने के लिए ही किया जाए। जल संसाधन विभाग के मैदानी अमले को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में तालाबों को भरवाना सुनिश्चित करें और किसी भी स्थिति में निस्तारी के अलावा अन्य उपयोग के लिए पानी न दिया जाए। साथ ही पानी के दुरुपयोग और अपव्यय को रोकने के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। यदि नहर के पानी का उपयोग रबी में धान की सिंचाई जैसे अन्य कार्यों में किया गया तो संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्किन ग्राफ्टिंग से मरीज के पलक का सफल पुनर्निर्माण

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में एक बार फिर जटिल चिकित्सा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए डॉक्टरों

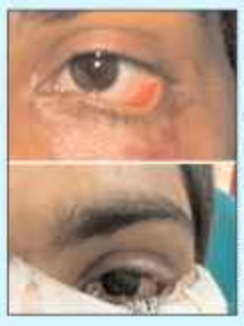

की टीम ने 22 वर्षीय युवक को नई दृष्टि और सामान्य जीवन की ओर लौटने का अवसर प्रदान किया है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई आंख की निचली पलक का सफल ऑपरेशन कर मरीज को बड़ी राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक दिसंबर 2025 में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। हादसे में उसकी आंख की निचली पलक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे वह अपनी आंख पूरी तरह बंद नहीं कर पा रहा था। प्रारंभिक उपचार के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद वह सिम्स के नेत्र रोग विभाग पहुंचा। नेत्र विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के दौरान पलक पर बने पुराने कठोर निशान (स्कार टिश्यू) को सावधानीपूर्वक हटाया गया। इसके बाद पलक की संरचना को पुन: सामान्य करने के लिए उन्नत स्किन ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया। सर्जरी अत्यंत जटिल थी, क्योंकि ग्राफ्ट का आकार बड़ा था। इसके बावजूद विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक स्किन ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण कर पलक और गाल के हिस्से का पुनर्निर्माण किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की आंख की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और अब वह सामान्य रूप से देख पा रहा है। पलक भी पूरी तरह से बंद हो रही है, जिससे चेहरे की विकृति दूर हो गई है। इस सफल सर्जरी में डॉ. सुचिता सिंह, डॉ. प्रभा सोनवानी, डॉ. कौमल देवांगन, डॉ. विनोद ताम्रकनंद, डॉ. डेलीना नेल्सन, डॉ. संजय चौधरी एवं डॉ. अनिकेत सहित नर्सिंग स्टाफ सिस्टर संदीप कौर तथा नेत्र, सर्जरी एवं निश्चेतना विभाग की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सर्जरी पूरी तरह सफल रही है। मरीज की पलक सामान्य स्थिति में लौट आई है और आंख की कार्यक्षमता भी बहाल हो गई है। चेहरे की विकृति समाप्त होने से मरीज और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली तथा सिम्स के चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि सिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर निरंतर बेहतर हो रहा है।

सुशासन तिहार की तैयारियों में तेजी

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा बैठक में दिए सख्त निर्देश

बिलासपुर। जिले में 1 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक लेकर व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक में बताया कि सुशासन तिहार के तहत जिलेभर में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 31 शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिविरों के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और समस्याओं की अग्रिम पहचान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पिछले वर्ष के लंबित प्रकरणों की पुन: समीक्षा करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक योजना में संतृप्ति स्तर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित सीमांकन प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उन्होंने अपर कलेक्टरों को स्वयं तहसील स्तर पर जाकर एक-एक मामले की समीक्षा करने को कहा। साथ ही बकाया भू-अर्जन की राशि का समय पर

वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जल प्रबंधन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह उपयुक्त समय है, जब लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। सभी नगरीय निकायों में पेयजल की नियमित जांच कराने, तालाबों के गहरीकरण को जनसहयोग से कराने तथा जल संरक्षण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बरगद, पीपल, नीम और करंज जैसे जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने और इसे जनआंदोलन का रूप देने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए नागरिकों से अधिकाधिक स्व-गणना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद सरल है और लगभग 5 मिनट में पूर्ण की जा सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट में लंबित जवाब-दावा प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक 24 अप्रैल को

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति बैठक 24 अप्रैल 2026 को अपरान्ह 3 बजे से जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में होगी। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा, अनुबंधित कार्यों की समय सीमा में वृद्धि, समूह जल प्रदाय योजनाओं की अनुबंधित देयकों की भुगतान और समय विस्तार पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही संशोधित स्वीकृति, सपोर्ट एवं जल गुणवत्ता से संबंधित सामग्री क्रय, जिला तकनीकी इकाई के लिए समिति गठन तथा केएमएल फाइल तैयार करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हर घर जल के तहत एफएचटीसी के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अंतर, गर्मी के मौसम में 4 वाहनों की व्यवस्था एवं यूनिट विजिट, सीआईआरपी एवं स्त्रोत स्थायित्व की कार्ययोजना सहित कलेक्टर श्री अग्रवाल की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।

भीषण गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

■ लू से बचाव और उपचार के लिए जारी किए व्यापक दिशा-निर्देश

बिलासपुर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में लू के लक्षण, बचाव के उपाय, प्रारंभिक उपचार तथा अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लू (हीट स्ट्रोक) की संभावना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए समय रहते सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लू के प्रमुख लक्षणों में सिरदर्द, तेज बुखार, चक्कर आना, उल्टी, शरीर में दर्द, अत्यधिक गर्मी के बावजूद पसीना न आना, अत्यधिक प्यास लगना, पेशाब कम आना तथा बेहोशी शामिल हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करते हुए तुरंत आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। लू से बचाव के लिए नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, धूप में निकलते समय सिर और कान ढंकने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के, सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। अधिक पसीना आने पर ओआरएस घोल का सेवन करने तथा चक्कर या घबराहट होने पर छायादार स्थान पर आराम करने और ठंडे पेय पदार्थ लेने की भी सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर 104 आरोग्य सेवा केंद्र से निरूशुल्क परामर्श लेने को कहा गया है।लू से प्रभावित व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना, शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करना, पर्याप्त तरल पदार्थ देना तथा मरीज को हवादार स्थान पर लिटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गंभीर स्थिति में तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी शासकीय अस्पतालों को भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बाह्य रोगी विभाग में आने वाले मरीजों की लू के लक्षणों की जांच, कम से कम दो बेड आरक्षित रखना, वार्डों में कूलर या अन्य शीतलन व्यवस्था करना तथा ठंडे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक उपचार कक्ष में ओआरएस कॉर्नर स्थापित करने, पर्याप्त मात्रा में जीवनरक्षक दवाएं, इंट्रावेनस फ्लूइड और ओआरएस पैकेट उपलब्ध रखने तथा गंभीर मरीजों के लिए विशेष प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

ग्राम सभाओं के जरिए सहेजी जाएगी विरासत

■ ज्ञान भारत' अभियान से पांडुलिपि संरक्षण को नया बल

बिलासपुर। संस्कृति मंत्रालय की पहल 'ज्ञान भारतम् राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' के तहत देश की अमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए अब ग्राम स्तर पर भी व्यापक प्रयास शुरू हो गए हैं। इस अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित कर सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, संस्कृति, विज्ञान और दर्शन को संजोए रखने वाली पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'ज्ञान भारतम्' अभियान संचालित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से न केवल पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, बल्कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत 'ज्ञान भारतम् मोबाइल एप' विकसित किया गया है, जिसके जरिए कोई भी नागरिक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर पांडुलिपियों की जानकारी दर्ज कर सकता है। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत रूप से, मंदिर ट्रस्ट, विश्वविद्यालय या अन्य संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में भी पंजीयन कर सकते हैं। एप पर उपलब्ध पांडुलिपियों की तस्वीरें अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिशा में राज्य स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं बिलासपुर जिले में जिला स्तरीय समिति गठित कर अभियान को गति दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले में 8 मास्टर ट्रेनर और 494 अन्वेषकों की नियुक्ति कर उनका प्रशिक्षण भी पूरा किया जा चुका है। बिलासपुर में इस अभियान को ग्राम सभाओं तक ले जाकर एक अभिनव पहल की गई है।

डीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति के पूर्व मंगाई दावा-आपत्ति

बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 5 आवेदकों के आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। यदि आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत हो अथवा किसी प्रकार के अपराधिक या न्यायालीन मामले उनके विरूद्ध लंबित हो तो इसकी जानकारी उक्त समयावधि में बंद लिफाफे में या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी दे सकते है।डीईओ ने आगे बताया कि मस्तुरी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला उड़ागी में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत स्व. श्री दुर्गेश कुमार शुक्ला के परिवार से उनके पुत्र श्री शिवम शुक्ला, कोटा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सीस में व्याख्याता के पद पर कार्यरत स्व. श्री देवेन्द्र कुमार दीक्षित की पत्नी श्रीमती चन्द्रकिरण दीक्षित, बिल्हा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भाड़ी में व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्यरत स्व. श्री राकेश कुमार बाटवे की पत्नी श्रीमती रेनु बाटवे ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। इसी प्रकार मस्तुरी ब्लॉक के जनपद पंचायत मस्तुरी में सं.आत.ले.परी. एवं करा. अधिकारी के पद पर कार्यरत स्व. श्री भागवत प्रसाद सुमन के पुत्र श्री कृष्ण कुमार सुमन एवं तखतपुर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला लिम्ही में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत स्व. श्री मनोज कुमार श्रीवास के पुत्र श्री ओमकार श्रीवास ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकों के संबंध में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कक्ष क्रमांक 25 पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग प्रथम तल में निर्धारित अवधि में दिया जा सकता है।

भू-जल संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ....

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति स्रोतों की स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु भू-जल संवर्धन एवं एक्विफर पुनर्भरण तकनीकों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन विकासखंड मस्तुरी में किया गया। प्रशिक्षण में वरिष्ठ वैज्ञानिक बी. अभिषेक, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रूपेश धनंजय एवं एपीओ जिला पंचायत श्रीमती अनुराधा मिश्रा द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, सहायक अभियंता एवं उप अभियंताओं ने भाग लिया तथा एक्विफर रिचार्ज एवं जल स्रोत पुनर्भरण की उन्नत तकनीकों को समझा। प्रशिक्षण के अंतर्गत टीम द्वारा तीन ग्रामों में स्थल निरीक्षण कर लाइव डेमो किया

गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सरगांव में स्थित एक बड़े तालाब के अपस्ट्रीम क्षेत्र में जल उपलब्ध था। टीम द्वारा तालाब के डाउनस्ट्रीम स्थित पेयजल स्रोत (ट्यूबवेल) का निरीक्षण किया गया। भू-वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तालाब के अपस्ट्रीम में फ्रैक्चर, फॉल्ट लाइन चिन्हित की गई, जहां वर्षा जल एवं बांध का पानी प्रवेश करता है। उक्त स्थान पर इंजेक्शन वेल स्थापित करने हेतु उपयुक्त साइट चयनित किया गया, जिससे सीधे एक्विफर में जल पुनर्भरण होकर डाउनस्ट्रीम स्थित पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ किया जा सके। मस्तुरी के ग्राम जयरामनगर में स्थित दो तालाबों के निरीक्षण के दौरान ऊपरी तालाब सूखा एवं निचला तालाब निस्तारी उपयोग में पाया गया। ग्राम सरपंच द्वारा बताया गया कि ऊपरी तालाब के भरने पर सभी पेयजल स्रोत सुचारू रूप से चलते हैं। इस पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक ने बताया कि ऊपरी तालाब स्वयं एक परकोलेशन टैंक की तरह कार्य करता है, अत: यहां इंजेक्शन वेल की आवश्यकता नहीं है। ग्राम परसदा वेद के तालाब में पर्याप्त जल उपलब्ध था एवं इसका कैचमेंट क्षेत्र विस्तृत पाया गया। रन ऑफ एवं नहर जल के प्रवेश बिंदु पर फ्रैक्चर, फॉल्ट लाइन चिन्हित कर इंजेक्शन वेल हेतु उपयुक्त स्थान चयनित किया गया। इससे तालाब के डाउनस्ट्रीम स्थित पेयजल स्रोतों (ट्यूबवेल) का पुनर्भरण सुनिश्चित होगा, जिससे जल जीवन मिशन अंतर्गत ओएचटी एवं ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली को स्थायित्व मिलेगा।

नन्हे कवियों ने जीता दिल:पृथ्वी दिवस समारोह में अनाया और अमोघ रहे खास आकर्षण.....

बिलासपुर। विश्व पृथ्वी दिवस पर विवेकानंद उद्यान, सिम्स चौक में आयोजित भव्य फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता 2026 उत्साह और पर्यावरण जागरूकता के संदेश के साथ संपन्न हुई। पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति, बिलासपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने प्रकृति संरक्षण को लेकर रचनात्मक प्रस्तुतियां दीं, वहीं समाज में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी, अध्यक्षता डॉ. विनय कुमार पाठक तथा विशेष अतिथि के रूप में डॉ. राघवेन्द्र कुमार दुबे, डॉ. रमेश चन्द्र श्रीवास्तव और डॉ. विष्णु कुमार तिवारी उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष डॉ. विवेक तिवारी ने आयोजन को बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। नन्हे कवियों ने बिखेरा शब्दों का जादू – इस आयोजन की सबसे खास झलक रही दो नन्हे कवियों का सम्मान, जिन्होंने अपनी रचनाओं से सभी का दिल जीत लिया। अनाया शुक्ला (9 वर्ष) को उनकी स्वरचित कविता वृक्ष हमारा प्राण सखी के लिए सम्मानित किया गया। उनकी कविता में प्रकृति और जीवन के गहरे संबंध को बेहद सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। वहीं अमोघ शुक्ला (7 वर्ष) ने एक वृक्ष लगाओ कविता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। उनकी मासूम लेकिन सार्थक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया। दोनों नन्हे कवियों को मंच पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जहां उपस्थित अतिथियों ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य

के लिए शुभकामनाएं दीं। बच्चों ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश – फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों ने जल संरक्षण, वन्य जीवन और हरित पृथ्वी जैसे विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रियांश राज, शौर्या सिन्हा, सनाया सिन्हा, मायशा, तृप्ति राज, अनाया शुक्ला, अमोघ शुक्ला, आद्या पाण्डेय और मयांश सहित कई प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता योद्धाओं का भी हुआ सम्मान – कार्यक्रम में रतनपुर के ऐतिहासिक दुलहरा सरोवर में स्वच्छता अभियान चलाने वाले शीतल प्रसाद पाटनवार और डीएलएस महाविद्यालय के एनएसएस प्रभारी शेख अफरीदी व उनकी टीम को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों ने इन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश – मुख्य अतिथि पूजा विधानी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और बच्चों के माध्यम से यह संदेश समाज में व्यापक बदलाव ला सकता है। वहीं डॉ. विनय कुमार पाठक ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शत्रुघन जेसवानी ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन सचिव बालगोविन्द अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और शहरवासी मौजूद रहे। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि छोटे कदम और नन्ही आवाजें भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती हैं।

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को

■ अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी

■ जिले में 34 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 119 केंद्रों में देंगे परीक्षा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 26 अप्रैल को जिले के 119 केंद्रों में सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा में 34 हजार 396 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा का समय सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन सुरक्षा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 9.30 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर आना होगा, जबकि गहरे रंग जैसे काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग और चॉकलेटी रंग के कपड़े प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए निर्धारित समय से पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

सुख, समृद्धि देने वाला रोहिणी व्रत का विशेष महत्व

रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण व्रत है इस व्रत को जैन समुदाय के लोग करते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता हैं। इसलिए इसे व्रत को रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर रोहिणी व्रत का पारणा किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। रोहिणी व्रत एक वर्ष में 12 होते हैं अर्थात् यह प्रत्येक महीने में आता है। फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है क्योंकि रात को भोजन नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है। अगर उचित अवधि की बात करें तो यह 5 वर्ष और 5 महीने है। इस व्रत का समापन उद्यापन द्वारा ही किया जाता है। यह व्रत पुरुष और स्त्रियां दोनों कर सकते हैं। हालांकि, स्त्रियों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना गया है। जैन समुदाय में यह मान्यता है कि यह व्रत विशेष फल देता है तथा कर्म बन्धन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है।

रोहिणी व्रत पूजा विधि :

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। इसके बाद सभी नित्यकर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि कर घर की साफ-सफाई करनी चाहिए। गंगाजल युक्त पानी से स्नान-ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आमचन कर अपने आप को शुद्ध करें। पहले सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें। इस व्रत के दौरान जैन धर्म में रात का भोजन करने की मनाही होती है। फलाहार सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए।

रोहिणी व्रत में क्या करें और क्या न करें?

सूर्योदय से पहले स्नान करें।
व्रत का संकल्प लें
चंद्र देव की पूजा करें।
सात्विक आहार लें (फलाहार)
तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन-प्याज आदि से परहेज करें। झूठ न बोलें, क्रोध न करें। नशे या किसी भी बुरे व्यवहार से बचें। नींद में अधिक समय न बिताएं

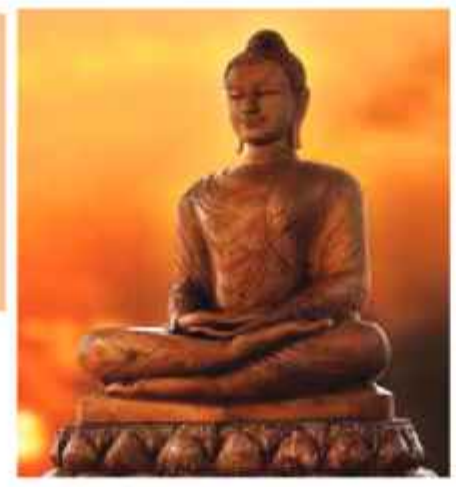

रोहिणी व्रत कितनी बार किया जाना चाहिए?

रोहिणी व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी फलदायी होता है। यदि जीवन में मानसिक बेचैनी, नौकरी मे बाधा या वैवाहिक समस्या हो तो यह व्रत बहुत लाभ देता है। यह व्रत चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र मे किया जाता है जो मन, भावनाओं और वैवाहिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। इस व्रत को करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह ज्योतिषीय दृष्टि से चंद दोष, मानसिक अस्थिरता, और वैवाहिक समस्याओं में राहत देने वाला एक प्रभावी उपाय है।

लहंगे के मिरर वर्क को सुरक्षित रखें

क्या आपके पास भी है वो खूबसूरत मिरर वर्क वाला लहंगा, जिसे आप बार-बार पहनना चाहती हैं पर डरती हैं कि कहीं इसका वर्क खराब न हो जाए? तो चिंता छोड़िए, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए ऐसे सिम्पल टिप्स जिनसे आपका लहंगा बना रहेगा नया जैसा, हर बार। पैकिंग के ये आसान तरीके आपके लहंगे के मिरर वर्क को सुरक्षित रखेंगे। तो, देखते हैं कैसे आप अपने पसंदीदा लहंगे को कर सकती हैं पैक, बिना किसी झंझट के।

सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल

जब भी आप अपने मिरर वर्क वाले लहंगे को पैक करने जा रहे हों, तो एक छोटी सी टिक अपना लें। बस उसे कोई नरम कपड़े में, जैसे कि मलमल या फिर वो सॉफ्ट टिश्यू पेपर में, अच्छे से लपेट दें। इससे आपके लहंगे के मिरर पर कोई खरोंचे वगैरह नहीं आएंगी, जो आम तौर पर पैकिंग के दौरान आ जाती हैं।

रोल करके रखें

लहंगे को फोल्ड करने की जगह, रोल करके रखें। इससे उस पर सिलवटें कम पड़ेंगी और मिरर वर्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

हवादार पैकेजिंग

अपने लहंगे को किसी ऐसे बैग में रखो जहां हवा आसानी से आ-जा सके। इससे क्या होगा ना, कि लहंगा हमेशा नया जैसा बना रहेगा और उसमें से मोल्ड या फंगस वगैरह का कोई चांस ही नहीं होगा। बस, इतना करके आप अपने प्यारे लहंगे को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हो।

अलग-अलग रखें

जब भी हो सके, अपने मिरर वर्क वाले लहंगे के अलग-अलग हिस्सों को एक-दूसरे से अलग रखने की कोशिश करो। इससे जो मिरर्स हैं, वो एक-दूसरे से टकराकर खराब नहीं होंगे। ये एक सिम्पल सा कदम है, पर इससे आपके लहंगे का मिरर वर्क लंबे समय तक सेफ रहेगा।

वैक्यूम बैग्स का उपयोग

लंबे समय तक स्टोरेज के लिए वैक्यूम बैग्स में लहंगे को सील कर देना चाहिए ताकि यह धूल और नमी से सुरक्षित रहे। और लहंगे जल्दी खराब नहीं होंगे।

किचन में फ्रिज रखने की सही दिशा

घर किचन में फ्रिज भी जरूर होता है। ये व्यक्ति के जीवन का भाग बन चुका है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति फ्रिज को किचन में किसी भी दिशा में रख देता है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र में किचन में फ्रिज को रखने की दिशा का वर्णन किया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार, फ्रिज किचन में किस दिशा में रखना चाहिए? साथ ही जानते हैं इससे जुड़े कुछ नियम।

किचन में फ्रिज रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, फ्रिज को आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा में रखें। ये दिशा ही फ्रिज रखने की सबसे सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। वास्तु में बताया गया कि बिजली से संबंधित सामान रखने के लिए आग्नेय कोण सबसे अच्छी दिशा होती है। इसके साथ ही किचन के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण-पश्चिम में भी फ्रिज रखा जा सकता है। इन दिशाओं में भारी उपकरण रखने से घर में स्थिरता और सुख-समृद्धि रहती है। हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा, उत्तर या फिर पूर्व दिशा में फ्रिज को न रखें। ऐसा करने से बुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

फ्रिज से जुड़े अन्य नियम

किचन में फ्रिज को इस तरह से रखें कि उसका दरवाजा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर खुले। फ्रिज को गैस स्टोव या चूल्हे के बिल्कुल पास नहीं रखें। फ्रिज में कभी भी खराब या सड़ा हुआ खाना न रखें। इसे हमेशा साफ रखें। फ्रिज में जरूरत जितना ही सामान रखें।

फल खाने के अपने कई फायदे हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी फल को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि फलों को कब और कैसे खाना चाहिए। कुछ लोग रात को भी फल खाते हैं तो कई लोग सुबह खाली पेट फल खाना हेल्दी मानते हैं, लेकिन क्या सुबह खाली पेट हर तरीके के फल खाएं जा सकते हैं? इस बारे में डायटिशियन से जानते हैं।

सुबह खाली पेट कौन से फल नहीं खाने चाहिए

सुबह खाली पेट फल खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल है जिनको कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फल फायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं। इनको सुबह खाने से एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्या भी होने का रिस्क रहता है।

सुबह खाली पेट खट्टे फल खाने से बचें

सुबह खाली पेट खट्टे फल खाने से बचना चाहिए। जैसा संतरा, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड अधिक होता है। इससे पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे अपच से लेकर गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से गैस्ट्रिक समस्या है, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों में खट्टा फल खाने से पाचन की समस्या और भी बढ़ सकती है। वैसे तो केले में काफी एनर्जी होती है। इसको हमेशा खाने के कुछ घंटे बाद खाना चाहिए। कभी भी केला खाली पेट नहीं खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि खाली पेट खाने पर इसमें मौजूद मैग्नीशियम और प्राकृतिक शुगर शरीर में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। केला खाने से शरीर में शुगर लेवल भी तेजी से बढ़ सकता है। इसी तरह आम को भी कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आम में शुगर होती है। खाली पेट आम खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, डायबिटीज के मरीजों को इसको खाली पेट नहीं खाना चाहिए।

आज का राशिफल

मेष राशि - आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। ज्वेलरी या कीमती वस्तुओं से जुड़े कारोबार में आज सामान्य से अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े किसी पुराने विवाद या मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा।

वृषभ राशि - आज का दिन आपके लिए प्रगति दिलाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपके सकारात्मक व्यवहार से अधिकारी प्रभावित होंगे और कोई विशेष जिम्मेदारी या उपहार भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। किसी नए अवसर से धन लाभ की संभावना बन सकती है।

मिथुन राशि - आज का दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यतीत हो सकता है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। जमीन या संपत्ति से जुड़ा कोई सौदा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा।

कर्क राशि - आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजना बना सकते हैं। खेल से जुड़ी महिलाओं को आज किसी उपलब्धि या सम्मान मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार का वातावरण शांत रहेगा और बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।

सिंह राशि - आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। काम के प्रति समर्पण आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। इंटीरियर डिजाइनिंग या क्रिएटिव क्षेत्र के छात्रों को इंटर्नशिप का अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि - आज आपका मन उत्साहित और सकारात्मक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और वेतन वृद्धि के संकेत भी हैं। मार्केटिंग या व्यापार से जुड़े लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। किसी बुजुर्ग की मदद करने से आपको मानसिक संतोष मिलेगा।

तुला राशि-आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। बुक्स या शिक्षा से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। व्यापार में अच्छी बिक्री से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

वृश्चिक राशि - आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नए काम की योजना बनाने का विचार भी आ सकता है। नया घर या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है, जिससे आर्थिक योजनाओं में बदलाव होगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। व्यापार में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और काम में प्रगति देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और परिवार की मदद से योजनाएं सफल होंगी। समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए संतुलित भोजन और नियमित जांच जरूरी होगी।

मकर राशि - आज का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से उन्हें पार कर लेंगे। अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। मित्रों और अधिकारियों का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कुंभ राशि- आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और काम में व्यस्तता बनी रहेगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यशैली से अधिकारी प्रभावित होंगे। समाज से जुड़े मुद्दों पर आपकी राय लोगों को प्रभावित कर सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकता है। थोड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। खेल से जुड़े लोगों को अपने कोच से विशेष प्रशिक्षण मिलने की संभावना है। किसी छोटे प्रयास से बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।

- ज्योतिष गुरु पंडित अतुल शास्त्री

स्किन पर झाइयां क्यों निकलती हैं? क्या है इसका इलाज

झाइयां त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है, जिसमें चेहरे या शरीर के कुछ हिस्सों पर भूरे या काले रंग के छोटे-छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे अक्सर गालों, नाक, माथे और ठुड्डी के आसपास ज्यादा नजर आते हैं। शुरुआत में झाइयां हल्की होती हैं, लेकिन समय के साथ इनका रंग गहरा भी हो सकता है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह त्वचा की सेंसिटिविटी या असंतुलन का संकेत भी हो सकती है। झाइयों के साथ त्वचा का रंग असमान दिखना, चेहरे पर दाग-धब्बे बढ़ना या त्वचा का फीका पड़ना जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। लंबे समय तक धूप में रहने वाले लोग, हॉर्मोनल बदलाव से गुजर रही महिलाएं और त्वचा की सही देखभाल न करने वाले लोगों में भी झाइयां होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए त्वचा में दिखने वाले ऐसे बदलावों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी होता

त्वचा पर झाइयां निकलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण लंबे समय तक धूप के संपर्क में रहना माना जाता है। सूरज की तेज किरणें त्वचा में मेलेनिन की मात्रा को बढ़ा सकती हैं, जिससे चेहरे पर काले या भूरे धब्बे बनने लगते हैं। इसके अलावा हॉर्मोनल बदलाव भी झाइयों का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी, बढ़ती उम्र या हॉर्मोन से जुड़ी अन्य स्थितियों के दौरान त्वचा पर ऐसे धब्बे दिखाई दे सकते हैं।

कई बार गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, त्वचा की सफाई ठीक से न करना और प्रदूषण भी त्वचा को प्रभावित करते हैं। तनाव, खराब लाइफस्टाइल और पौष्टिक डाइट की कमी भी त्वचा की सेहत पर असर डाल सकती है। इन सभी कारणों से त्वचा की प्राकृतिक चमक कम हो सकती है और झाइयां धीरे-धीरे दिखाई देने लगती हैं।

झाइयों के इलाज के लिए सबसे पहले त्वचा की सही देखभाल करना जरूरी होता है। डॉक्टर की सलाह से कुछ खास क्रीम या स्किन ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, जो त्वचा के दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करते हैं। कई मामलों में सनस्क्रीन का नियमित उपयोग भी जरूरी बताया जाता है, ताकि धूप का असर त्वचा पर कम पड़े। इसके अलावा कुछ स्किन ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पील या अन्य प्रक्रियाएं भी डॉक्टर की सलाह से की जा सकती हैं।

हालांकि किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है, ताकि त्वचा के प्रकार के अनुसार सही इलाज किया जा सके।

ये भी जरूरी

त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सही स्किन केयर रूटीन अपनाना जरूरी है। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, चेहरे को साफ रखना और ज्यादा देर तक धूप में रहने से बचना त्वचा की सुरक्षा में मदद करता है। इसके साथ ही संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी त्वचा की सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं। तनाव को कम करना भी त्वचा पर पॉजिटिव असर डालता है।

लौकी कोफ्ता बनाने के लिए 5 आसान टिप्स

भारतीय रसोई में कई ऐसे जायकेदार व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनका स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद होता है। ऐसी ही एक डिश का नाम लौकी कोफ्ता करी है। लौकी की सब्जी को देखकर भले ही आप नाक-मुंह सिकोड़ते हों लेकिन उससे बने कोफ्ते देखकर हर किसी के मुंह में पानी भर जाता है। हालांकि अकसर घर की महिलाओं की यह शिकायत रहती है कि उनसे करी तो टेस्टी बनती है लेकिन लौकी के कोफ्ते या तो टाइट बनते हैं या फिर इतने सॉफ्ट की करी में ही घुलकर बिखर जाते हैं। जिससे ना सिर्फ कोफ्तों का स्वाद बल्कि मूड भी खराब हो जाता है। लौकी के कोफ्ते बनाना किसी बारीक कलाकारी से कम नहीं है, जहां स्वाद और बनावट के बीच एक बहुत महीन संतुलन साधना पड़ता है। एक परफेक्ट कोफ्ता वही है जो बाहर से अपना आकार बनाए रखे, लेकिन चम्मच लगाते ही मखमली एहसास के साथ टूट जाए। अगर आप भी हलवाई जैसा वही जायका और बनावट घर पर चाहते हैं, तो बस कुछ छोटी लेकिन जरूरी किचन टिप्स का ध्यान रखें।

1. लौकी का पानी पूरी तरह निचोड़ें

लौकी को कद्दूकस करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद उसे मलमल के कपड़े या हाथों से जितना संभव हो उतना निचोड़ें। लौकी में बहुत अधिक पानी होता है। ऐसा करने से उसमें मौजूद पानी निकल जाएगा, जिससे लौकी के कोफ्ते गीले होकर टूटेंगे नहीं। कद्दूकस की हुई लौकी के पानी को आप इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करके स्वाद और पोषण दोनों को बनाए रख सकती हैं।

2. बेसन की सही मात्रा और तरीका

ज्यादा बेसन डालने से कोफ्ते 'रबड़' जैसे सख्त हो जाते हैं, और कम डालने से वे बिखर जाते हैं। ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखें कि कोफ्ते बनाने के लिए बेसन डालने से पहले उसे हल्का भून लें। इस टिप को फॉलो करने से कोफ्तों में सौंधापन आता है और कम बेसन में भी अच्छी बाइंडिंग होती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि कोफ्ते का मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि वह बस हाथ में शेप ले सके, वह आटे की तरह सख्त नहीं होना चाहिए।

3. थोड़ा सा मोयन या दही

कोफ्तों को अंदर से जालीदार और नरम बनाने के लिए मिश्रण में एक चम्मच गरम तेल या एक चम्मच गाढ़ा दही मिलाएं। इससे कोफ्ते अंदर से सूखते नहीं है और करी को अच्छी तरह सोखते हैं।

4. तलने का सही तापमान

कोफ्तों को हमेशा मीडियम आंच पर फ्राई करें। तेज आंच पर कोफ्ते फ्राई करने से वो ऊपर से काले और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके विपरीत अगर आंच बहुत धीमी होगी, तो कोफ्ते बहुत ज्यादा तेल सोखकर भारी हो जाएंगे।

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को अच्छे से साफ करें

लिपस्टिक महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने का एक आसान और असरदार तरीका है। ये ना सिर्फ चेहरे की चमक बढ़ाती है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ावा देती है। आजकल महिलाएं डेली रूटीन में लिपस्टिक लगाती हैं, चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या कोई छोटी-सी मीटिंग ही क्यों न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना लिपस्टिक लगाने से होंठों पर बुरा असर भी पड़ सकता है, अगर उसकी सही केयर न की जाए तो? अगर आप भी रोजाना लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिसकी जानकारी यहां दी गई है आइए जानते हैं इनके बारे में

होंठों की सफाई जरूरी है

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को अच्छे से साफ करें। पुराने लिपस्टिक के पार्टिकल्स, धूल-मिट्टी या ऑयल की परत हटाना जरूरी होता है, जिससे नई लिपस्टिक ठीक से सेट हो और होंठ हेल्दी रहें।

लिप बाम का बेस लगाएं

लिपस्टिक से पहले लिप बाम लगाने से होंठ हाइड्रेट रहते है। यह ड्रायनेस और क्रैकिंग को रोकता है और लिपस्टिक भी स्मूद लगती है।

प्राइमर या कंसीलर का करें इस्तेमाल

लंबे समय तक लिपस्टिक को टिकाए रखने के लिए होंठों

पर हल्का सा कंसीलर या लिप प्राइमर लगाएं। इससे लिपस्टिक की शेड भी उभरकर आती है।

अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक चुनें

हमेशा ऐसी लिपस्टिक का चुनाव करें जो त्वचा के सही हो और हानिकारक केमिकल्स से मुक्त हो। लोकल या सस्ती लिपस्टिक से एलर्जी और पिग्मेंटेशन की समस्या हो सकती है।

डार्क शेड्स का सीमित इस्तेमाल करें

गहरे रंग की लिपस्टिक में पिगमेंट ज्यादा होता है, जो लंबे समय में होंठों को डार्क बना सकता है। इसलिए हल्के और नेचुरल शेड्स को भी शामिल करें।

फुटहामुड़ा नहर परियोजना से बदलेगी कुकरेल क्षेत्र की सिंचाई तस्वीरः मिश्रा

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सोमवार को फुटहामुड़ा नहर से प्रभावित ग्राम माकरदोना, मोहलई, पथर्रीडीह, छुही एवं सालेभाट के कृषकों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं सुनीं तथा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान लाभान्वित कृषक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि यह परियोजना पूर्ण होने पर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए तथा प्रभावित कृषकों के लंबित मुआवजा प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन हेमलाल कुरैशिया ने जानकारी दी कि नगरी विकासखण्ड में सिलयारी डायवर्सन वियर एवं फुटहामुड़ा नहर निर्माण हेतु प्रारंभिक स्वीकृति 17.56 करोड़ रुपये की थी, जिसे विभिन्न कारणों से संशोधित करते हुए वर्तमान में 73.94 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

परियोजना से 1940 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी, जिससे कुकरेल क्षेत्र के 22 ग्राम सीधे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य नहर की कुल लंबाई 19.74 किलोमीटर तथा लघु नहरों की लंबाई 18.61 किलोमीटर है। वर्तमान में नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें 750 मीटर से 9330 मीटर तक के हिस्से में लगभग 20 प्रतिशत तथा 9330 मीटर से 19740 मीटर तक के हिस्से में लगभग 15 प्रतिशत भौतिक प्रगति दर्ज की गई है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण एवं नहर लाइनिंग कार्य निर्धारित समय-सीमा 4 मार्च 2027 तक पूर्ण किया जाएगा। बैठक में कृषकों ने मुआवजा भुगतान में विलंब, भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं एवं निर्माण कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों को प्रमुखता से रखा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए परियोजना को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि यह योजना क्षेत्र के कृषि विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से किसानों को स्थायी लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने तथा शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला संशोधन बिल पर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं ने बताया

बलौदाबाजार। महिला संशोधन बिल के संबंध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक पहल बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ शालिनी राजपूत ने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सशक्त बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेंगे। जिला प्रभारी अमित साहू ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह बिल उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। जिलाध्यक्ष आनंद यादव ने इसे देश के विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने से समाज और राष्ट्र दोनों सशक्त होंगे। प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने बिल के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर कुर्मी समाज केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता वर्मा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रणम पाण्डे मणि कांत मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल तरुण वर्मा पुरुषोत्तम सोनी रितेश श्रीवास्तव नीलम सोनी भी उपस्थित रहे।

समस्याओं को लेकर तारिणी ने की कलेक्टर से मुलाकात

धमतरी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने ग्रामीणों के साथ विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर चर्चा की जिस पर कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कुरुद विकासखंड के ग्राम पंचायत हथबंद मे सचिव के तानाशाही पूर्ण रवैया व उनके द्वारा शासकीय कार्यो का सही तरीके से क्रियान्वयन नही किए जाने को लेकर सरपंच के द्वारा उक्त सचिव पर कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत सिर्वे मे महिला सरपंच के अधिकारों का हनन, फर्जी तरीके से शासकीय धन का दुरुपयोग, खेल मैदान निर्माण, विद्यालय परिसर में बनाए गए नाली निर्माण को हटाने की मांग व अन्य पंचायतो से आवास निर्माण की मांग, प्राथमिक कृषि साख समिति के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण सहित व्याप्त गंभीर समस्याओं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफउच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने बताया कि कुरुद विकासखंड के विभिन्न ग्रामो से आये समस्याओं को लेकर जिलाधीश से चर्चा किया गया जिस पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

नगर पंचायत से बिना अनुमति काम्प्लेक्स निर्माण, नहर के अस्तित्व पर उठ रहे सवाल

धमतरी। नगर पंचायत नगरी में नवनिर्माणाधीन काम्प्लेक्स के डायवर्सन के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी। इस पत्र को 24 दिन के प्रभार में रहे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नजरअंदाज करते हुए डायवर्सन प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया जिसके तहत संबंधित व्यक्ति द्वारा जल संसाधन विभाग के नहर के करीब काम्प्लेक्स निर्माण करवाया जा रहा है जो कभी भी नहर के सुरक्षा पर खतरा साबित हो सकता है। इस नहर से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को पानी दिया जाता है। यदि इस काम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है तो ऐसे में किसानों को पानी नहीं मिलने की समस्या सामने आ सकती है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहर के अस्तित्व को बचाये रखने के लिये संबंधित निर्माण को जनहित में अविलंब डिस्मेंटल किया जाना चाहिये। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है जिसकी वजह से फिलहाल काम बंद है। अब देखना यह है कि बिना अनुमति के काम्प्लेक्स का निर्माण करने वाले व्यक्ति पर आगे पंचायत क्या कार्यवाही करती है? खबर के मुताबिक जल संसाधन विभाग के अधीन आने वाले माइनर नहर के समीप काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन काम्प्लेक्स के जमीन के डायवर्सन को लेकर जब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में आवेदन दिया गया था, तो उस समय उक्त प्रकरण में लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, ग्राम नगर निवेश विभाग जैसे विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र लगनी चाहिये थी जिसमें से बिजली विभाग, लोनिवि विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में निर्माणकर्ता सफल हो गया। लेकिन प्रकरण में ग्राम तथा नगर निवेश विभाग का कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है वहीं नगर पंचायत ने उक्त जमीन के डायवर्सन पर आपत्ति भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद भी प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा डायवर्सन आदेश पारित कर दिया गया। आश्चर्य की बात है कि जिस जमीन को राजस्व

अधिकारी ने डायवर्सन आदेश पारित किया है वह ग्राम तथा नगर निवेश क्षेत्र में आता है और ऐसे में उक्त विभाग के बिना एनओसी और नगर पंचायत के आपत्ति के बाद प्रकरण में डायवर्सन आदेश पारित होने से कई सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर जागरूक लोगों ने भी आवाज बुलंद की है और उन्होंने कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से भारी उम्मीदें लगाई है। इनका कहना है कि जब तक उक्त प्रकरण की विवेचना नहीं हो जाती और प्रकरण में ग्राम नगर निवेश का पक्ष नहीं लिया जाता, तब तक उक्त निर्माण कार्य को रोका जाये अथवा डिस्मेंटल करा दिया जाये। ऐसे अनेक प्रकरण प्रभारी अधिकारी ने डायवर्सन के किये हैं जिसे लेकर भी कहा जा रहा है कि जितने भी डायवर्सन हुए हैं, उसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है।

उसके बाद भी उसमें आदेश किया जाना संदेह के दायरे में है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि जिस काम्प्लेक्स का निर्माण नहर के समीप जारी था जिसे नगर पंचायत की आपत्ति के बाद वर्तमान में काम बंद है। उक्त नहर वर्षों पुरानी है जिसकी सुरक्षा की जवाबदारी जल संसाधन विभाग की है। लेकिन इस विभाग से भी उक्त निर्माणकर्ता ने अनुमति प्राप्त नहीं की है जिस पर भी लोगों की मांग है कि इस निर्माण कार्य को जल संसाधन विभाग के अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही कराया जाना चाहिये था। खबर के मुताबिक उक्त व्यक्ति जो निर्माण कार्य नहर के समीप करवा रहा है वह नियमानुसार नहीं है क्योंकि काम्प्लेक्स निर्माण के पश्चात आने-जाने का मार्ग जरूरी होता है। भारी वाहनों के साथ साथ छोटी वाहनें भी उक्त काम्प्लेक्स में आना-जाना करेंगे जिससे वर्षों पुरानी नहर का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

लेकिन इसकी चिंता निर्माणकर्ता को नहीं है। राजस्व न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में किये गये आदेश के जांच की मांग को लेकर लोग अब लामबद्ध हो रहे हैं और शीघ्र ही इसकी शिकायत कलेक्टर को कर उक्त निर्माण कार्य को तुड़वाने की मांग करेंगे। यदि इस पर भी कार्यवाही नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्र के लोग राजधानी जाकर मुख्यमंत्री से भेंट कर संदिग्ध रूप से निर्माणाधीन काम्प्लेक्स की शिकायत करेंगे। साथ ही साथ काम्प्लेक्स निर्माण के नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किये जाने के संबंध में उचित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। काम्प्लेक्स निर्माण को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता से दूरभाष पर संपर्क कर उनका पक्ष लिया गया तो उनका कहना था कि हमारे विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति को दो-तीन बार नोटिस जारी किया जा चुका है। पुनः एक बार उन्हें नोटिस जारी किया जायेगा। इस संबंध में नगर पंचायत नगरी के सीएमओ यशवंत वर्मा के मोबाईल नंबर 7000616268 में दोपहर 12.01 बजे एवं 12.21 बजे दो बार मोबाईल लगाकर उनसे संपर्क कर उनका पक्ष लिये जाने का प्रयास किया गया परंतु वर्मा द्वारा मोबाईल रिसीव नहीं किया गया जिसके कारण उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।

बलौदाबाजार नगर में निवास रत जनता को मिलेगी सीधे कर की डिजिटल जानकारी लगाए जाएंगे 5010 मकानों में क्यू आर बोर्ड

नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने क्यू आर बोर्ड किया लोकार्पित

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवास रत करदाताओं को घर के बाहर लगाए गए क्यू आर कोड बोर्ड के माध्यम से नगर पालिका को प्रदाय किए जाने वाले राशि की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी, इसी योजना के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन के द्वारा डिजिटल क्यू आर कोड बोर्ड का लोकार्पण किया गया, लोकार्पण के दौरान सभापति पार्षद हरजीत सिंह सलूजा व कन्हैया सेन सहित अन्य उपस्थित थे , नगरीय क्षेत्र में निवास रत करदाताओं को पूर्ण रूप से प्रदाय किए जाने वाली सुविधा के लिए यह क्यू आर बोर्ड से निवास निकाय को प्रदाय किए जाने वाली समेकित कर ,संपत्ति कर, एवं जलकर , की जमा किए जाने वाली राशि का विवरण प्राप्त किया जा सकता है, जिसमे कर दाता का नाम व मकान का विवरण दिखेगा, डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते कदम से जनता को भविष्य में इस कर कोड से शिकायत एवं अन्य के साथ अपने स्वयं के मकान की अदा की जाने वाली राशि का संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकेगा, डिजिटल क्यू आर कोड बोर्ड वर्तमान में लगभग नगर पालिका के क्षेत्र में 5010 निजी मकान में लगाया जाएगा जो सीधे नगर पालिका से जुड़े होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने जन सामान्य के लिए इस डिजिटल बोर्ड को लाभ कारी बताया, व नगर पालिका में अनावश्यक आने से बच कर घर से ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे व यह क्यू आर पूर्ण रूप से पारदर्शिता पूर्ण बताया गया, व हितग्राहीअपने मोबाइल के एक क्लिक से मकान के टैक्स की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उस राशि को जमा भी कर सकते हैं, इस प्रयास को सार्थक बताया गया मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सभी नगरीय निकायों में निवास रत जनता को इस डिजिटल क्यू आर कोड बोर्ड का लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए जन सामान्य को सुविधा का विस्तार किए जाने डिजिटल बोर्ड हर मकान में लगाया जा रहा है , जिसमे क्यू आर प्रिंट रहेगा, डिजिटल बोर्ड को नगर पालिका अध्यक्ष कक्ष में लोकार्पित किए जाने के दौरान पार्षद प्रतिनिधि रवि फेकर, भारत भूषण साहू नगर पालिका के राजस्व विभाग प्रभारी प्रसून शर्मा, स.रा.नी.सतेंद्र सिन्हा, गुरुदत्त तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं सीईओ चंद्राकर के नेतृत्व में भू-जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहा है कार्य

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उईके एवं जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर के नेतृत्व में जिले में जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे मैनपुर विकासखण्ड के इस पहल से प्रेरणा लेकर जल संरक्षण के उपाय अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित करें। जिले में लगातार गिरता भू-जल स्तर अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अनियमित वर्षा, बढ़ते जल दोहन और वर्षा जल के अपर्याप्त संचयन के कारण कई क्षेत्रों में जल स्तर में कमी आ रही है। जिससे भविष्य में पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है। जनपद पंचायत मैनपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण की दिशा में -मोर गांव मोर पानी- अभियान के तहत सोखता गड्ढा निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिससे वर्षा के जल को जमीन में समाहित कर भू-जल स्तर को पुनर्भरित करने का प्रयास किया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत बजाड़ी, मुचबहाल, कोयबा, इंदागांव, हरदीभाटा, गोपालपुर, गुढ़ियारी, धनोरा, अमलीपदर, गोलमाल एवं कोकराझार में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में महिला समूहों, पशु सखियां, कृषि सखी, सीआरपी, पीआरपी एवं अन्य मैदानी कार्यकर्ताओं की भूमिका सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के कार्य किए जाएं, तो गिरते जल स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सोखता गड्ढे वर्षा जल को सीधे जमीन में पहुंचाकर जल संचयन का प्रभावी माध्यम होगा।

कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों की वैकल्पिक व्यवस्था पर प्रशिक्षण

गरियाबंद। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं अटारी जबलपुर के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र, गरियाबंद द्वारा अक्षय तृतीया (अक्ती तिहार) के पावन अवसर पर कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्य म का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर, गंगूराम साहू सहित जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिकगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्य म का शुभारंभ पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना कर किया गया। संस्था प्रमुख डॉ. मनीष चौरसिया ने बताया कि जिले में संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी खेती की ओर प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्य म निरंतर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदलते कृषि परिदृश्य में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना समय की आवश्यकता है। मृदा वैज्ञानिक मनीष आर्या ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर डीएपी के अत्यधिक उपयोग से मृदा में पोषक तत्वों का असंतुलन बढ़ रहा है, जिससे दीर्घकाल में उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और एकीकृत पोषण प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। प्रशिक्षण के दौरान नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरक, म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम, पीएसबी, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही हरी खाद, केंचुआ खाद एवं नील हरित शैवाल के उपयोग को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। किसानों को सलाह दी गई कि वे हर 2-3 वर्ष में मृदा परीक्षण कराएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करें तथा जिंक एवं सल्फर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें।

राज्य कृषि विपणन मंडी अंतर्गत उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को

धमतरी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आगामी 26 अप्रैल को छग राज्य कृषि विपणन मंडी अंतर्गत उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित किया जाएगा। अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि धमतरी जिले के 41 केन्द्रों में सुबह 10 से दोपहर 12.15 बजे तक यह परीक्षा आोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार सुबह 9.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को व्यापम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने.अपने परीक्षा केन्द्रों में समय पर पहुंचने कहा गया है।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस व विपक्षी दलों को महिलाओं से कैसा खतरा समझ से परे : अशोक जैन

बलौदाबाजार। लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष के दल व कांग्रेस ने साथ नहीं दिया जिससे यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका इससे यह बात साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी और विपदल का चेहरा कितना साफ है, और महिलाओं की हित की बात करना महज दिखावा ही साबित हुआ है, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने उक्त बातें अपनी प्रतिक्रिया में दी जब महिलाओं को 33त की भागीदार बनाने के लिए भाजपा ने लोकसभा में यह अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम से देशभर से अत्यधिक संख्या में महिला सांसद चुनकर आती और महिलाओं की शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होती, साथ ही महिला सशक्तिकरण से महिला स्वावलंबी जीवन के मार्ग में आगे बढ़कर अन्य महिलाओं के हित में विचार से देश में महिलाओं की ताकत बढ़ेगी,इसमें महिलाओं को मदद मिलती पर इन सब से परे रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के खुशी व उत्साह को कम कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में लाकर विपक्ष के सहयोग से भारत देश की महिलाओं को लाभ मिलता इससे परे विपक्ष ने साथ नहीं दिया, देश व राज्य की महिलाओं को मिलने वाला हक और अधिकार को समाप्त करने व महिलाओं को पीछे धकेलने में विपक्षी कांग्रेस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसके विपरीत आने वाले समय में देश की नारी शक्ति भी कांग्रेस पार्टी से अपना बदला लेगी, आरक्षण विधेयक महिलाओं के हित में था इससे विपक्ष को खतरा दिखा यह समझ से परे है। पर स्वयं की मजबूती से ज्यादा महिलाओं की मजबूती भी देश के लिए बेहद जरूरी है,यह कांग्रेस को समझना चाहिए, -जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी- का अर्थ होता है जननी का अर्थ जन्म देने वाली -मां- जो जन्म देती है और जन्मभूमि का अर्थ वह मिट्टी है जहां हम जन्म लिए हैं, यह दोनों स्वर्ग के सुख से भी अधिक मूल्यवान है नारी शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए इसके महत्व व पुण्य प्रताप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से जानती व समझती है तभी महिलाओं के हित में आरक्षण विधेयक को लाया गया भविष्य में इसे महिलाओं की शक्ति के दम पर पुनः बहुमत से विधेयक को स्वीकृति दिलाने भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को पास करके महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाएगी ।

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पाण्डुका में नवागंतुक विद्यार्थियों का मनाया गया स्वागत एवं प्रवेश पर्व

गरियाबंद। 20 अप्रैल सोमवार को पीएम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पाण्डुका में नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत एवं प्रवेश पर्व मनाया गया। नवागंतुक विद्यार्थियों (छठवीं कक्षा) का प्रवेश पर्व तिलक चंदन लगाकर और मिठाई प्रदान करके शाला प्रवेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के प्राचार्या महिमा सिन्हा ने विस्तार से विद्यालय के शैक्षणिक एवं आवासीय परिवेश, मेस व्यवस्था, खानपान सुविधाओं, पालकों के नियम, टेलीफोन सुविधा के साथ अनुशासन आदि की जानकारी दी। डी.के. सिंह ने विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनकर और समाज का सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके उपरांत विद्यार्थियों को किताब, स्टेशनरी सामग्री, बेडिंग सामग्री का वितरण करके विद्यार्थियों को सदन प्रभारी से परिचय करवा कर सदनों में प्रवेश दिया। शाला प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षकाएं यू.के. राठिया, रविशंकर आर्मो, ए. ममता, आर.एन.सोन, अनिल कुमार राणा, मनोष कुमार मानिकपुरी, सुसंजू साहू, सुरीतिका सिंह, सुपल्लवी किन्डो, आनंद सिंह, प्रफुल्ल सोनी, डॉ. ठाकुर राम साहू, लेख राम, अनिता दास राजेन्द्र कुमार पाठक, अमर सिंह ठाकुर।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com